मुंबई (महाराष्ट्र) से प्रकाशित
हिन्दी दैनिक
उत्तरशक्ति
हर खबर निष्पक्षता के साथ
मुंबई
वर्ष: 8 अंक 301
गुरुवार, 21 मई 2026
मूल्य 3 रुपए, पृष्ठ-6
RNI NO. MAHHIN/2018/76092
email ID- uttarshaktinews@gmail.com
www.uttarshaktinews.com

भारत और इटली आतंकवाद, साइबर अपराध, जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे: पीएम मोदी

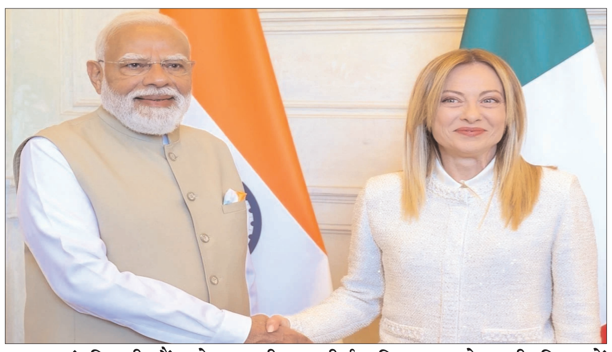

रोम, 20 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की कूटनीतिक यात्रा का अंतिम चरण इटली की राजधानी रोम में भारत और इटली के संबंधों के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला के साथ व्यापक वार्ता कर दोनों देशों के संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के नए स्तर तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोम को दुनिया में अनंत शहर के रूप में जाना जाता है और उनकी लोकसभा सीट काशी की पहचान भी इसी प्रकार की है। उन्होंने कहा कि जब दो प्राचीन सभ्यताएं मिलती हैं, तो बातचीत केवल किसी तय एजेंडे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें इतिहास की गहराई, भविष्य की झलक और मित्रता की सहजता दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इटली के बीच चर्चा केवल औपचारिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साझा मूल्यों और दीर्घकालिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2000 के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय इटली यात्रा है और इस यात्रा ने लंबे अंतराल को समाप्त करते हुए संबंधों को नई गति दी है। मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के संबंध अब निर्णायक चरण में पहुंच चुके हैं और दोनों देश स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा साझा भविष्य की सोच के आधार पर विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं।

हम आपको बता दें कि दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।

संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत और इटली आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी, अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक रणनीतिक स्थिरता को भी सहयोग का प्रमुख आधार बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला के साथ भी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, नवाचार और संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-2029 के तहत सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया।

हम आपको यह भी बता दें कि भारत और इटली ने विनिर्माण तथा निवेश के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने कहा कि मेड इन इटली और मेक इन इंडिया पहल के बीच स्वाभाविक तालमेल मौजूद है।

राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 20 मई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बढ़ते महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच मितव्ययिता उपायों की घोषणा करने के बाद विदेश यात्रा पर जाने के लिए जमकर निशाना साधा और उन पर भारत की आर्थिक व्यवस्था को बेचने का आरोप लगाया। बहुजन स्वाभिमान सभा में सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने प्रधानमंत्री की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की कि उन्होंने देश की जनता को सोना न खरीदने और विदेश यात्रा न करने की सलाह दी, जबकि कुछ ही समय बाद वे पांच देशों के दौरे पर निकल पड़े। उन्होंने आगामी आर्थिक तूफान की अपनी चेतावनी को दोहराते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और सरकार देश को बचाने में सक्षम नहीं होंगे।

उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी जनता से कहते हैं: सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, इलेक्ट्रिक वाहन चलाओ। यह सब कहने के तुरंत बाद, नरेंद्र मोदी करोड़ों रुपये के विमान में सवार होकर विदेश रवाना हो जाते हैं, जबकि जनता चुपचाप देखती रहती है। इस बीच, देश में एक आर्थिक तूफान मंडरा रहा है। भीषण महंगाई होगी, हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी और उर्वरकों की कमी होगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को बेच दिया है। उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था अंबानी, अडानी और अमेरिका के हाथों में सौंप दी है। अब एक आर्थिक तूफान आने वाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार आपको बचा नहीं पाएंगे। वे रोएंगे और कहेंगे कि यह मेरी गलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, गलती सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है क्योंकि उन्होंने इसे (संविधान को) नष्ट कर दिया है।

इसके अलावा, कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से ईंधन की बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले कीमतों में कोई वृद्धि न होने का आश्वासन दिया था। चुनाव से पहले कहा गया था कि पेट्रोल या गैस की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। आज जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अंबानी भारत से पेट्रोल का निर्यात कर रहे हैं। अंबानी रूस से पेट्रोल खरीदते हैं और उसे बाहर बेचते हैं, और उस पैसे से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंड देते हैं। यही सच्चाई है। आगे, कांग्रेस नेता ने पूज्य वीर पासी और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और संविधान के अनुसार होना चाहिए।

बिजली कर्मियों का फूटा गुस्सा, निजीकरण और उत्पीड़न के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी

सुरेश गांधी

वाराणसी। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश की बिजली व्यवस्था को लेकर बिजली कर्मियों और प्रबंधन के बीच टकराव गहराता दिख रहा है। निजीकरण और कथित उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के विरोध में बुधवार को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले वाराणसी और गाजीपुर में जोरदार प्रदर्शन और जनजागरण सभाएं आयोजित की गईं। वाराणसी के भेलूपुर स्थित कार्यालय पर आयोजित सभा में कर्मचारियों ने प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तत्काल वार्ता और उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों को वापस लेने की मांग उठाई।

सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई से कर्मचारियों में भारी असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है। उनका आरोप है कि प्रबंधन बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के बजाय कर्मचारियों पर दबाव बनाने और दमनात्मक रवैया अपनाने में जुटा हुआ है।

समिति के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति व्यवस्था पहले से ही दबाव में है और कई स्थानों पर अव्यवस्था की स्थिति बन रही है। इसके बावजूद कर्मचारियों के सहयोग से समाधान तलाशने के बजाय टकराव की नीति अपनाई जा रही है।

संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि डाउनसाइजिंग के नाम पर वर्षों से कार्य कर रहे कम वेतन वाले संविदाकर्मियों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग के तहत नियमित पदों को भी समाप्त किया जा रहा है। इससे बिजली व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।

पदाधिकारियों का कहना था कि संविदाकर्मियों की संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा कर्मचारियों से लगातार 12 से 14 घंटे तक काम कराया जा रहा है। इसके बावजूद व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा और उपभोक्ताओं को शिकायतों के समाधान के लिए भटकना पड़ रहा है। संघर्ष समिति ने मांग की कि यदि गर्मी के मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी है तो प्रबंधन को तत्काल कर्मचारी संगठनों के साथ संवाद स्थापित कर ठोस कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई वापस लेने की भी मांग उठाई गई।

पकड़े गए घुसपैठियों को बीएसएफ को सौंपकर देश से बाहर निकाला जाएगा, बंगाल में नियम लागू : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

कोलकता, 20 मई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को एक ऐसी व्यवस्था लागू करने की घोषणा की, जिसके तहत राज्य पुलिस द्वारा पकड़े गए घुसपैठियों को निर्वासन के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही "पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो" ढांचे की भी घोषणा की। शुभेंदु के उत्तर बंगाल से लौटने के तुरंत बाद वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित प्रेस वार्ता में की गई इस घोषणा ने घुसपैठ और सीमा प्रबंधन पर नीतिगत रुख में तीखे बदलाव का संकेत दिया, जो लंबे समय से बंगाल में भाजपा के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक मुद्दों में से एक रहा है और नयी सरकार के एजेंडे के केंद्र में है। उन्होंने राज्य सचिवालय 'नबान्न' में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के अंतर्गत आने वाले समुदाय नयी व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेंगे, जबकि घुसपैठियों के रूप में पहचाने जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की ओर से पिछले साल लाए गए उस प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने की बात कही गई है। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 मई को राज्य सरकार को घुसपैठियों को सीधे बीएसएफ को सौंपने के संबंध में पत्र भेजा था, लेकिन पिछली सरकार इस महत्वपूर्ण प्रावधान को लागू करने में विफल रही। हमने अब इसे लागू कर दिया है।

शुभेंदु ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने सीएए का विरोध किया और केंद्र द्वारा बनाई गई व्यवस्था को लागू नहीं किया। सीएए के प्रावधानों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून के अंतर्गत आने वाले सात समुदाय, जो निर्धारित समयसीमा से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, "नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत सात समुदायों का नाम लिया गया है और जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक आए हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है तथा पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकती।" नागरिकता कानून के दायरे में आने वाले समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं, जो निर्धारित समयसीमा से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के चलते भारत आ गए थे।

शुभेंदु ने कहा कि अधिनियम के दायरे में न आने वालों को घुसपैठिया माना जाएगा। उन्होंने कहा, "राज्य पुलिस उन्हें हिरासत में लेगी और बीएसएफ को सौंप देगी।" शुभेंदु ने कहा कि इसके बाद बीएसएफ बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) के साथ समन्वय करके निर्वासन प्रक्रिया शुरू करेगी।

बंगाल में बीजेपी राज आते ही सड़क पर संग्राम, बुलडोजर एक्शन पर टीएमसी का 21 मई को विरोध प्रदर्शन

कोलकता, 20 मई। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने पश्चिम बंगाल में नवगठित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा फेरीवालों के जबरन निष्कासन और कथित तौर पर लागू की गई 'बुलडोजर संस्कृति' के खिलाफ 21 मई को कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की है। हावड़ा स्टेशन, सियालदह स्टेशन और बालीगंज के पास विरोध प्रदर्शन निर्धारित हैं, जिनमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। ये प्रदर्शन फेरीवालों और अल्पसंख्यक समुदायों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने के विरोध में होंगे। यह घोषणा पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बढ़ते राजनीतिक तनाव के मद्देनजर की गई है।

भारत बना दुनिया का सबसे गर्म देश, तपती गर्मी और लू से हर किसी का जीना मुहाल

नई दिल्ली, 14 मई। पूरा देश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है और उत्तर, मध्य तथा पूर्वी भारत के अनेक हिस्सों में तापमान लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। मंगलवार दोपहर को भी भारत ने वैश्विक तापमान चार्ट पर अपना दबदबा बरकरार रखा। दोपहर करीब 2:30 बजे अदक्कल्ल की लाइव तापमान रैंकिंग के अनुसार, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से सभी भारत में ही स्थित थे। यह देश भर में जारी भीषण गर्मी की लहर की तीव्रता और व्यापकता को रेखांकित करता है। रैंकिंग से पता चला कि दोपहर होते-होते तापमान में और वृद्धि हुई, यहां तक कि सूची में सबसे नीचे के शहरों में भी भीषण गर्मी दर्ज की गई, और यहां भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे स्पष्ट है कि गर्मी का दायरा कितना व्यापक हो चुका है।

इस सूची में केवल छोटे कस्बे ही नहीं, बल्कि देश के प्रमुख शहर भी शामिल रहे। नई दिल्ली, फरीदाबाद, चंडीगढ़, जम्मू, आगरा, अयोध्या, ग्वालियर, कोटा और रायपुर जैसे शहरों में भीषण लू का असर दिखाई दिया। दोपहर तक चंडीगढ़, जम्मू, बठिंडा, पठानकोट, बरेली, झांसी, कैथल और हरिद्वार जैसे कई शहर 46 डिग्री तापमान के दायरे में पहुंच गए थे।

DAKS REHAB CENTRE
(PARALYSIS PHYSIOTHERPHY CENTER AND OLD AGE HOME)
Contact us: 9820519851
विल्डिंग नंबर 3, प्लॉट नंबर 3, आदर्श घरकुल सोसायटी सायन कोलीवाडा जीटीबी नगर मुंबई-37
* Stroke/Paralysis/Complete Rehab Centre
* बाहर से आये रोगी और उनके परिजनो के ठहरने कि व्यवस्था
* वृद्ध लोगों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध
* DM/HT/THYROID इन सब से कैसे बचें
* NGO में मिलनेवाली सहायता को लोगों में देना
* चिकिस्ता उपकरणो को किराये और बिक्री सुविधा उपलब्ध
* एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध
* पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब सेंटर
* मरीजों के लिए घर पर 12 और 24 घंटे जीडीए परिचारक
* विशेषज्ञ डॉक्टरो से ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध
* मासिक ईएमआई के आधार पर व्यक्तीयों, परिवारो और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य निती की चिकिस्ता सुविधा उपलब्ध

TIWARI'S SARASWATI CLASSES
Since 1992
Parents' First Choice for 34+ Years
Prof. Dr. Dayanand Tiwari
Founder & Academic Director
ADMISSIONS OPEN
9th | 10th | 11th | 12th SCIENCE
NEET | JEE | MHT-CET
10 DAYS FREE DEMO
Attend Classes • Experience Our Teaching
Take Admission After Satisfaction
(No Hidden Conditions)
✓ 34+ Years of Academic Excellence
✓ Experienced & Dedicated Faculty
✓ Personal Attention
✓ Printed Notes & Regular Tests
✓ Strong Foundation for Boards & Competitive Exams
Santacruz Branch: 101 Sai Chambers, Opp. Santacruz Railway Station (East), Near Depot, Santacruz (E), Mumbai-400055
Sion Branch: Opp. SIES College (Old), Near Gurukripa Hotel, Sion (West), Mumbai
Limited Seats / Small Batch Size
CALL NOW: 7738007373

NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE
2nd Floor, Sheetal Bldg. Near Diamond Talkies, L. T. Road, Borivali (West) Mumbai - 400 092 Maharashtra
ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW

SMART CLASSROOM
(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered
• Std. XI & XII (Sci.)
• NEET
• JEE (Main & Advance)
• MHT-CET
• Polytechnic & Engg
• Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)
M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

अपराधमुक्त राजनीति से ही संभव है नया भारत-विकसित भारत

-ललित गर्ग

भारत आज एक ऐतिहासिक संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ओर देश विकसित भारत-2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व राजनीति और कूटनीति के केंद्र में उभर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय राजनीति में अपराध, धनबल और बाहुबल की बढ़ती पैठ लोकतंत्र की आत्मा को आहत कर रही है। यह विडंबना ही है कि जिस भारत को विश्वगुरु बनने का स्वप्न दिखाया जा रहा है, उसकी राजनीति अभी भी अपराधमुक्त नहीं हो सकी है। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए आंकड़ों ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। समाचार पत्रों में प्रकाशित एडीआर (ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट) की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल विधानसभा के लगभग 65 प्रतिशत विधायक आपराधिक मामलों वाले हैं, जबकि 61 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। रिपोर्ट के अनुसार 294 विधायकों में से 190 विधायकों ने अपने विरुद्ध आपराधिक मामले घोषित किए हैं तथा लगभग 142 विधायकों पर गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं के विरुद्ध अपराध और अन्य गंभीर मामले भी शामिल हैं।

यह केवल पश्चिम बंगाल की स्थिति नहीं है। संसद और देश की अनेक विधानसभाओं की स्थिति भी इससे बहुत अलग नहीं है। पिछले कुछ वर्षों के चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अनेक राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। लोकतंत्र के मंदिरों में अपराध और दागी छवि वाले लोगों की बढ़ती उपस्थिति आज राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। राजनीति मूलतः लोकसेवा, नैतिक नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण का माध्यम मानी गई थी। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने राजनीति को मूल्य आधारित दिशा दी। लेकिन समय के साथ राजनीति में वैचारिक प्रतिबद्धता का स्थान धीरे-धीरे चुनावी गणित, धनबल और प्रभावशाली समूहों ने लेना शुरू कर दिया। आज कई राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन में योग्यता, चरित्र और जनसेवा की बजाय ह्लजीतने की क्षमताह्व को प्राथमिकता देते दिखाई देते हैं। यही कारण है कि दागी छवि वाले व्यक्तियों को भी टिकट देने में संकोच नहीं किया जाता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की राजनीति में आने के बाद अनेक मंचों से राजनीति के अपराधीकरण पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने संसद में और सार्वजनिक मंचों पर कई बार कहा कि राजनीति को अपराधमुक्त बनाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अदालतों की आवश्यकता पर बल दिया। किंतु चिंता का विषय यह है कि आज भी लगभग सभी राजनीतिक दलों की स्थिति समान दिखाई देती है। चुनाव जीतने की मजबूरी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण दल अपराधी और दागी उम्मीदवारों को टिकट देने से परहेज नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है चुनावों का अत्यधिक खचीर्ला होना। आज चुनाव लड़ना सामान्य व्यक्ति की क्षमता से बाहर होता जा रहा है। बड़े संसाधनों वाले और आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोग चुनावी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय हो रहे हैं। दूसरा कारण है बाहुबल और प्रभाव का उपयोग। कई क्षेत्रों में आज भी राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए शक्ति प्रदर्शन को महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा कारण है न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति। गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों के वर्षों तक लंबित रहने के कारण आरोपी चुनाव लड़ते रहते हैं और जनप्रतिनिधि बन जाते हैं।

राजनीति में अपराधीकरण का दूसरा बड़ा पक्ष है धनबल। पश्चिम बंगाल विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि 61 प्रतिशत विधायक करोड़पति हैं। यह प्रवृत्ति पूरे देश में दिखाई देती है। संसद और विधानसभाओं में करोड़पति जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रश्न यह है कि क्या लोकतंत्र धीरे-धीरे सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर होता जा रहा है? यदि राजनीति केवल धनवान और प्रभावशाली वर्गों तक सीमित हो जाएगी तो लोकतंत्र की समावेशी भावना कमजोर होगी। इन परिस्थितियों में नागरिक समाज और लोकतांत्रिक संगठनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय मतदाता संगठन इस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास कर रहा है। इसके संस्थापक रिखबचंद जैन के नेतृत्व में लंबे समय से राजनीति को स्वच्छ और अपराधमुक्त बनाने की दिशा में जनजागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। संगठन मतदाता जागरूकता, नैतिक मतदान, स्वच्छ राजनीति और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। लोकतंत्र को केवल चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि मूल्य आधारित व्यवस्था मानते हुए यह संगठन समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि मतदाता केवल जाति, धर्म, क्षेत्र या दलगत निष्ठा के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवार के चरित्र और सार्वजनिक जीवन को देखकर मतदान करें। इसी प्रकार एडीआर (ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिपोर्ट) जैसे संगठन भी चुनावी पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की पृष्ठभूमि सार्वजनिक करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इन संगठनों के कारण आज मतदाताओं को उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों, संपत्ति और शिक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध हो रही है। यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय चुनाव आयोग भी इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीदवारों को शपथपत्र में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और देनदारियों की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। चुनाव आयोग लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। किंतु केवल औपचारिक प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। इन प्रयासों को अधिक तीव्र, व्यापक और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। आज आवश्यकता है कि राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन खड़ा किया जाए। इसके लिए कुछ ठोस कदम आवश्यक हैं- पहला, जिन उम्मीदवारों पर हत्या, बलात्कार, अपहरण, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप न्यायालय द्वारा तय हो चुके हों, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीर विचार होना चाहिए। दूसरा, जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के त्वरित निपटान हेतु विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वर्षों तक मुकदमे लंबित न रहें। तीसरा, राजनीतिक दलों को दागी उम्मीदवारों को टिकट देने पर जवाबदेह बनाया जाए। उन्हें सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार उपलब्ध होने के बावजूद दागी व्यक्ति को क्यों चुना गया। चौथा, चुनावी खर्च पर कठोर नियंत्रण और पारदर्शिता लाई जाए ताकि सामान्य और योग्य नागरिक भी राजनीति में प्रवेश कर सकें। पांचवां, मतदाता जागरूकता को जनांदोलन बनाया जाए। जब तक मतदाता स्वयं दागी उम्मीदवारों को अस्वीकार नहीं करेंगे, तब तक सुधार अधूरा रहेगा।

भारत आज जिस दिशा में बढ़ रहा है, वहां राजनीति की शुचिता और नैतिकता की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। यदि हम 2047 तक विकसित भारत बनना चाहते हैं, यदि हमें विश्वगुरु बनना है, यदि भारत को वैश्विक नेतृत्व करना है, तो राजनीति को अपराध और धनबल के प्रभाव से मुक्त करना ही होगा। आर्थिक शक्ति, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिष्ठा तभी सार्थक होगी जब लोकतंत्र की आत्मा सुरक्षित रहेगी। राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं, समाज निर्माण होना चाहिए। लोकतंत्र केवल वोटों का गणित नहीं, बल्कि विश्वास, नैतिकता और जनप्रतिनिधित्व की पवित्र व्यवस्था है। यदि राजनीति अपराधमुक्त होगी तो शासन अधिक पारदर्शी होगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा और राष्ट्रनिर्माण की गति भी तेज होगी। आज आवश्यकता केवल सरकारों या चुनाव आयोग के प्रयासों की नहीं है, बल्कि समाज, मतदाता संगठनों, नागरिक संस्थाओं, मीडिया और जागरूक नागरिकों के संयुक्त अभियान की है। भारतीय मतदाता संगठन जैसे प्रयास इसी दिशा में आशा की किरण हैं। इन प्रयासों को राष्ट्रीय स्वरूप देने की जरूरत है। भारत के विकसित भविष्य की आधारशिला केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि स्वच्छ राजनीति भी है। क्योंकि अपराधमुक्त राजनीति ही विकसित भारत, समृद्ध भारत और विश्वगुरु भारत की वास्तविक पहचान बन सकती है।

नॉर्वे की पत्रकार ने राहुल को ही इंटरव्यू के लिए क्यों फोन किया

अशोक भाटिया

हाल ही में मोदी के नार्वे के दौरे के बाद नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा के दौरान उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश की थी। ये पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब पीएम मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ मंच से उतर रहे थे। इसी दौरान का वीडियो शेयर करते हुए हेली लिंग ने पीएम मोदी से सवाल किया। फिर एक्स पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए भारत की प्रेस स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा। इस पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रिएक्ट किया। अब इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए हेली लिंग ने राहुल गांधी से इंटरव्यू की बात कही है।

बताया जाता है कि हेली लिंग ने ट्विटर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से संपर्क किया है। हेली लिंग ने राहुल गांधी से पूछा कि 'क्या वे मंगलवार को फोन पर इंटरव्यू के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता से पूछा कि नमस्ते, क्या आप मंगलवार को (नॉर्वे के समय के अनुसार) फोन इंटरव्यू के लिए उपलब्ध होंगे? यह जानना दिलचस्प होगा कि आप नॉर्वे की यात्रा को किस नजर से देखते हैं।' हेली लिंग एक्स पर राहुल गांधी की एक पोस्ट का जवाब दे रही थीं, जब उन्होंने पीएम मोदी के नॉर्वे दौरे का एक वीडियो शेयर किया।

राहुल गांधी ने हेली लिंग की इसी वीडियो पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए पीएम मोदी पर घबरा जाने और भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता, तो डरने की भी कोई बात नहीं होती। भारत की छवि का क्या होता है, जब दुनिया एक ऐसे पीएम को देखती है जो सवालों से घबराकर भाग जाते हैं?' वीडियो में, पत्रकार हेले लिंग को यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि पीएम मोदी, आप दुनिया की सबसे आजाद प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते?

हेली लिंग ने इस घटना का फुटेज अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर है। और फिलीस्तीन, अमीरात और क्यूबा जैसे देशों से मुकाबला कर रहा है। जिन ताकतों के साथ हम सहयोग करते हैं, उनसे सवाल पूछना हमारा काम है।

गौरतलब है कि नॉर्वे सिर्फ अपने खूबसूरत बफीर्ले समुद्र तटों और मछलियों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि उसकी एक सालाना आदत भी है- पूरी दुनिया को यह बताना कि तुम सब गलत कर रहे हो! इसे 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' (दुनिया में प्रेस की आजादी की रैंकिंग) कहा जाता है। इस लिस्ट में भारत का हाल बहुत बुरा है। वह इस सूची में फिलिस्तीन और वेनेजुएला के बीच कहीं है। जिनमें से एक देश गुलाम है और दूसरा आधा गुलाम। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश इसमें हम जैसे ही हैं। जैसे दक्षिण एशियाई सब एक जैसे दिखते हैं। इसमें तुर्की भी है, जहां के राष्ट्रपति एर्दोगन मजे-मजे में पत्रकारों को जेल भेज देते हैं। भारत इस लिस्ट में 157वें नंबर पर है और नॉर्वे हमेशा की तरह नंबर वन पर! क्योंकि नॉर्वे में बहुत आजादी है- दुनिया में सबसे ज्यादा, शायद जरूरत से ज्यादा।

वैसे आप किसी नॉर्वे वाले से भारत के लिए बहुत गर्मजोशी की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश है ही हाड़ कंपा देने वाला ठंडा। खैर, अब कहानी में एंट्री हुई है बेबाक और सुनहरे बालों वाली हेली लेन की। मिस लेन एक ऐसे अखबार या वेबसाइट में लिखती हैं जिसे खुद नॉर्वे के ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं पढ़ा। वह एक ऐसे देश के बारे में लिख रही हैं जहां नार्वे वाले कभी घूमने नहीं आएंगे। और यह सब उन्होंने एक ऐसी ज्वाइंट मीटिंग में किया जो कायदे से कोई सवाल-जवाब वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ही नहीं।

यह फर्क समझना जरूरी है। दो बड़े नेताओं की ऐसी ज्वाइंट मीटिंग सिर्फ फोटो खिंचवाने (फोटोऑप) के लिए होती है। कूटनीति का थिएटर, न कि तीखी पत्रकारिता का मैदान। दुनिया का हर पत्रकार यह बात जानता है। सिवाय शायद हेली लेन के, जिन्होंने सोचा कि नरेंद्र मोदी पर प्रेस फ्रीडम को लेकर चिल्लाने का यही सबसे सही मौका है। मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया और वह कमरे से बाहर चले गए। जब कोई आपके फोटो खिंचवाने के दौरान इस तरह चिल्लाए, तो वहां से चले जाना ही सबसे सही तरीका है।

लेकिन हेली इतने पर ही नहीं थमीं। उन्होंने लिफ्ट तक उनका पीछा किया। फिर घर जाकर इस बारे में ट्वीट कर दिया। उन्होंने लिखा, ∞नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं सुना। नॉर्वे प्रेस की आजादी में पहले नंबर पर है, जबकि भारत 157वें स्थान पर फिलिस्तीन, यूएई और क्यूबा से मुकाबला कर रहा है। हमारा काम उन ताकतों से सवाल करना है जिनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं।

हेली की बातें दिलचस्प सोच की गवाही देती हैं। कि नॉर्वे का भारत के साथ हाथ मिलाना एक नैतिक भूल है और इसके लिए हेली जैसी पत्रकार का टोकना जरूरी है। जबकि सच यह है कि ठीक उसी समय नॉर्वे की सरकार भारत के साथ कई बिजनेस डील साइन कर रही थी। नॉर्वे की सरकार ने खुद पीएम मोदी को न्योता दिया था, वहां के राजा ने उनसे हाथ मिलाया था। और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के बाद यह माना कि भारत बिजनेस करने के लिए एक बढ़िया देश है। लेकिन हेली के मन में सवाल थे -'Helle YeÔh'!

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब भी विदेश पत्रकारों के सामने होते हैं तो भारत का अपमान किए बिना नहीं रहते हैं। अपने विवादित बयानों से कभी वह खालिस्तान अलगाववादियों के जमीन तैयार कर देत हैं तो कभी चीन की वाहवाही करते हैं। इस बार उन्होंने भारत के लोकतंत्र का अपमान किया है। शायद यही सोच कर नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग ने उन्हें अपने विवादित इंटरव्यू के लिए चुना।

ऐसे कई मौके है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी विदेशी पत्रकारों के सामने भारत की आलोचना करते रहते है। जर्मनी के बर्लिन में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र की भाजपा सरकार पर तंज कसा था। इसके पहले अमेरिका यात्रा के दौरान बोस्टन यूनिवर्सिटी में भारतीय चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए समझौता करने वाला बताया। इस बयान के बाद यह सवाल फिर से उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की छवि को खराब कर रहे हैं? पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने कई बार विदेशी मंचों का इस्तेमाल भारत को लेकर विवादास्पद बयान देने के लिए किए हैं। इन बयानों पर अक्सर बीजेपी और अन्य दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मसलन, बोस्टन में उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर जो कुछ भी कहा है, उसे उनकी भारत बदनाम यात्रा कहा जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के नेशनल प्रेस क्लब में कहा कि ह्यभारत में लोकतंत्र पिछले 10 सालों से टूटा (ब्रोकेन) हुआ था, अब यह लड़ रहा है। दरअसल, इन चुनावों में 10 साल बाद कांग्रेस को लोकसभा चुनावों में विपक्ष के नेता का पद हासिल हो पाया था, क्योंकि वह 99 सीटों पर पहुंची थी। ऐसे में राहुल पर यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या 2014 और 2019 में देश में जो चुनाव हुए, उसमें देश की जनता ने वोट नहीं डाला था? उनका यह कहना लोकतंत्र की मूल भावना पर ही सवाल उठाता है।

सितंबर 2023 में राहुल गांधी ने ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन में कहा कि भारत में फुल स्केल एसॉल्ट हो रहा है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं की निष्पक्षता पर संदेह जताया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में भेदभाव और हिंसा बढ़ रही है। इस तरह के बयान भारत की अंदरूनी राजनीति को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाते हैं। राहुल गांधी यह क्यों भूल जाते हैं कि भारतीय चुनाव आयोग ने ही वे चुनाव संपन्न करवाए हैं, जिनके दम पर वह आज विपक्ष के नेता पद पर बैठे हुए हैं।

मई 2022 में लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थाएं परजीवी बन गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डीप स्टेट (CBI, ED) भारत को चबा रहा है। यहां डीप स्टेट का मतलब सरकार के अंदर छिपे हुए ऐसे ताकतवर लोग हैं जो अपने फायदे के लिए काम करते हैं। राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान जैसे अस्थिर लोकतंत्र से भी कर दी। अगस्त 2018 में यूके और जर्मनी में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि वे देशभक्त नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वे जनता के गुस्से का इस्तेमाल देश को नुकसान पहुंचाने में कर रहे हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के एक चुने हुए प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप था। इसे विदेशी मंच पर कहना स्वाभाविक रूप से विवाद पैदा करने वाला रहा।

मार्च 2018 में मलेशिया में राहुल गांधी ने नोटबंदी को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो इस प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंक देते। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह प्रधानमंत्री होते तो वह ऐसा नहीं करते। 2018 में ही सिंगापुर में ली कुआन यू स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में डर और नफरत का माहौल है। उन्होंने कहा कि बहुलता की विचारधारा खतरे में है। जनवरी 2018 में बहरीन में ठफ्फसम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बेरोजगारी से निपटने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि इसका असर सड़कों पर गुस्से और नफरत के रूप में दिख रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह समुदायों के बीच नफरत फैलाने में जुटी है।

सितंबर 2017 में अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ टॉप 100 कंपनियों के लिए काम कर रही है। 2017 में ही अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत अब वह नहीं रहा जहां हर कोई कुछ भी कह सकता है। उन्होंने विदेश की धरती पर भारत में फ्री स्पीच की स्थिति पर संदेह पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भारत में सहनशीलता खत्म हो गई है।

राहुल गांधी का यह तर्क रहा है कि वे भारत की असली तस्वीर दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन, आलोचना और बदनामी में एक बारीक फर्क होता है। एक राष्ट्रीय नेता को यह समझना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिए गए बयान सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे भारत की छवि, निवेशकों के भरोसे और वैश्विक कूटनीतिक संबंधों पर भी असर डालते हैं।

प्रेस फ्रीडम के बहाने ओस्लो में कैसे बना भारत की साख का वैश्विक तमाशा

-अजय कुमार

नॉर्वे सिर्फ अपने ठंडे, बफीर्ले समुद्र तटों और मछलियों के निर्यात के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि उसकी एक सालाना वैश्विक आदत भी है पूरी दुनिया की क्लास लेना और यह बताना कि तुम सब लोकतंत्र का ककहरा गलत पढ़ रहे हो। इसे कूटनीतिक हलकों में 'वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' कहा जाता है। इस फेहरिस्त में भारत की रैंकिंग का हाल बहुत अच्छा नहीं रहा है और हम 157वें पायदान पर खड़े दिखते हैं। लेकिन इस बार ओस्लो से जो कहानी आई, वह सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी नहीं थी, बल्कि उसमें एक सनकी कूटनीति, सोशल मीडिया का उथलापन और हमारी अपनी पुरानी 'गौरववादी' ग्रंथियों का एक अजीब घालमेल था। पूरी कहानी की मुख्य किरदार बनीं सुनहरे बालों वाली पत्रकार हेल लिंग, जो वहां के एक ऐसे अखबार से जुड़ी हैं जिसे खुद नॉर्वे के बहुसंख्यक लोगों ने शायद ही कभी पढ़ा हो। वह एक ऐसे देश के मुखिया के सामने तीखे सुर में चिल्ला रही थीं, जहां के भूगोल और राजनीति का उन्हें बहुत सतही अंदाजा था।

यह पूरा वाकया दोनों प्रधानमंत्रियों की एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हुआ, जिसे कूटनीति की भाषा में 'फोटो-ऑप' कहा जाता है। दुनिया का हर मंझा हुआ पत्रकार जानता है कि यह जगह गंभीर या खोजी सवाल-जवाब के लिए नहीं, बल्कि आपसी समझौतों पर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने का एक कूटनीतिक थिएटर होती है। मगर हेल लिंग ने इसे अपने लिए 'कंटेंट' बनाने का सही मौका समझा। जब प्रधानमंत्री कमरे से बाहर जाने लगे, तो उन्होंने चिल्लाते हुए प्रेस की आजादी पर तंज कसा और फिर इतने पर ही नहीं थमीं, बल्कि लिफ्ट तक उनका पीछा किया। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बहाने भारत को कटघरे में खड़ा करते हुए कई पोस्ट दाग दिए। सामान्य स्थिति में इसे एक उतावली पत्रकार की बचकानी हरकत मानकर टाला जा सकता था, लेकिन हमारे राजनयिक तंत्र ने यहीं पर बड़ी नासमझी कर दी।

भारतीय दूतावास ने अति-आत्मविश्वास में आकर उसी शाम हेल लिंग को एक औपचारिक प्रेस ब्रीफिंग में आमंत्रित कर लिया। लगा कि भारतीय पक्ष बड़ी दिलदारी और लोकतांत्रिक बड़प्पन दिखाना चाहता है, लेकिन वह कदम कूटनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हुआ। जब उस ब्रीफिंग में पत्रकार ने तीखे लहजे में पूछा कि दुनिया भारत पर भरोसा क्यों करे, तो हमारे विदेश मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने सीधे और तार्किक जवाब देने के बजाय एक लंबा-चौड़ा ऐतिहासिक व्याख्यान शुरू कर दिया। जवाबों में अचानक सरस्वती नदी की प्राचीन सभ्यता, शतरंज के खेल का आविष्कार, योग की महत्ता और कोरोना काल की वैक्सीन डिप्लोमेसी का जिक्र होने लगा। इसे कूटनीति नहीं कहते; यह तो ऐसा लगा जैसे कोई विदेश मंत्रालय किसी अंतरराष्ट्रीय प्रेस वार्ता को प्राचीन भारत के इतिहास पर स्कूल का कोई प्रोजेक्ट समझने की भूल कर बैठा हो। जब आप तीखे कूटनीतिक सवालों के जवाब में 'प्राचीन गौरवासन' का सहारा लेते हैं, तो आप एक ही समय में कमजोर और बड़बोले, दोनों नजर आने लगते हैं।

राजनयिकों के दिमाग में यह साधारण सी बात नहीं आई कि इस तीखेपन का रुख मोड़ा जा सकता था। उस पत्रकार से पूछा जाना चाहिए था कि अगर भारत भरोसे के लायक नहीं है, तो आपकी अपनी नॉर्वेजियन सरकार ठीक उसी समय हमारे साथ अरबों डॉलर की व्यापारिक डील क्यों साइन कर रही थी? वहां के राजा ने भारतीय प्रधानमंत्री से हाथ क्यों मिलाया और वहां की संसद ने इन समझौतों पर सहमति क्यों जताई? मगर कड़े और हुआ कि माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया और पत्रकार एक बार गुस्से में कमरे से बाहर भी संक्षिप्त कूटनीतिक जवाब की जगह इतिहास का पाठ पढ़ाया गया, जिसका नतीजा यह चली गईं। इस कूटनीतिक रायते को और फैलाने का काम हमारे घरेलू इंटरनेट और सोशल मीडिया ब्रिगेड ने किया। सोशल मीडिया पर यूजर्स दो धड़ों में बंट गए। एक वर्ग ने हेल लिंग के पुराने चीनी झुकाव वाले लेखों और अमेरिकी प्रशासन की आलोचनाओं को ढूंढ निकाला और उन्हें 'विदेशी एजेंट' या 'चीनी प्रॉक्सी' करार दिया। उनकी चुप्पी और अचानक एक्स पर आए 'ब्लू टिक' को एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश के सबूत के तौर पर पेश किया गया। हालांकि पत्रकार ने बाद में सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ अपनी एक स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारने के लिए पैसे देकर वह सब्स्क्रिप्शन लिया था और वह इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं। इंटरनेट ने इस सफाई को दरकिनार कर दिया, लेकिन इस पूरी ट्रोलिंग का उलटा असर यह हुआ कि सोमवार तक महज 800 फॉलोअर्स वाली एक साधारण कमेंटेटर अचानक 17 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'प्रेस फ्रीडम' का नया चेहरा बन गई।

भारतीय राजनीति ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में देर नहीं लगाई। विपक्ष के शीर्ष नेताओं ने इस घटना के वीडियो को साझा करते हुए सरकार की छवि पर सवाल उठाए और पूछा कि जब प्रधानमंत्री दुनिया के सामने सवालों से बचते हैं, तो देश की साख का क्या होता है। हालांकि, विपक्ष का यह तर्क भी थोड़ा कमजोर था, क्योंकि दुनिया के किसी भी परिपक्व लोकतंत्र में कोई प्रधानमंत्री किसी विदेशी नेता के साथ जॉइंट फोटो सेशन के शोर में इस तरह चिल्लाकर पूछे गए असंगत सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होता। असली समस्या प्रधानमंत्री का उस शोर में जवाब न देना नहीं था; असली समस्या भारत के भीतर पिछले 11 सालों से बनी वह व्यवस्था है जहां कोई औपचारिक, बिना स्क्रिप्ट वाली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जहां मीडिया खुलकर कोई भी सवाल पूछ सके। हमारे पास सैकड़ों टीवी चैनल जरूर हैं, लेकिन उनके पास पूछने के लिए सीधे सवाल नहीं हैं। इसी चुप्पी और कूटनीतिक तंत्र की बड़बोली घबराहट ने विदेशी मीडिया को भारत पर उंगली उठाने का एक आसान मौका दे दिया। तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। इस पूरे विवाद के बाद नॉर्वे के एक प्रमुख अखबार ने नस्लवाद की सारी हदें पार करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री का एक बेहद आपत्तिजनक कार्टून छाप दिया, जिसमें भारत को फिर से 'सांप-सपेरों' के पुराने औपनिवेशिक चश्मे से देखने की कुंठा साफ नजर आई। खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का मसीहा बताने वाले देश के मीडिया एथिक्स वहां आकर दम तोड़ गए। जो देश तकनीक, डिजिटल यूपीआई क्रांति और जीवन रक्षक दवाओं के लिए भारत पर निर्भर है, उसका मीडिया आज भी 140 करोड़ की आबादी वाले देश को उसी पुरानी सामंती सोच से आंक रहा है। लब्बोलुआब यह है कि न तो फोटो-ऑप के दौरान उस विदेशी पत्रकार का वह ड्रामा पत्रकारिता था, न हमारी सभ्यता वाला वह लंबा व्याख्यान कूटनीति था, और न ही इंटरनेट की वह अंधी ट्रोलिंग देश का सम्मान बचा रही थी। इस पूरे प्रकरण में सबने सिर्फ अपने हिस्से की राजनीतिक और डिजिटल रोटियां सेंकीं, और जो सच कड़वे सवाल के रूप में लिफ्ट के बंद दरवाजों के पीछे छूट गया था, वह आज भी वहीं खड़ा है।

पश्चिम बंगाल में ओबीसी कोटे पर नए फैसले से सुलगती सामाजिक और सियासी बिसात

-संजय सक्सेना

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए हालिया बदलाव ने देश के सबसे संवेदनशील और पुराने विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है आरक्षण, तुष्टिकरण और सामाजिक न्याय का असल चेहरा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने जिस तरह से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) सूची को लेकर कड़ा कदम उठाया है, वह महज एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि दशकों से चली आ रही 'वोटबैंक पॉलिटिक्स' की बुनियाद पर सीधा प्रहार है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार ने मई 2024 में आए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक आदेश को जमीन पर उतारा है, जिसने राज्य में बिना किसी वैज्ञानिक सर्वे और ठोस डेटा के थोक के भाव बांटे गए ओबीसी प्रमाण पत्रों को असंवैधानिक करार दिया था। नई सरकार का पहला बड़ा राजनीतिक दांव यह रहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में पिछली ममता बनर्जी सरकार द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया। इस एक फैसले ने साफ कर दिया कि नई व्यवस्था अब अदालत के रुख के साथ खड़ी है और 2012 के बाद से सामाजिक न्याय के नाम पर बुने गए उस जाल को पूरी तरह ध्वस्त करने जा रही है, जिसे विपक्षी दल 'मुस्लिम सब-कोटा' का शॉर्टकट बताते रहे हैं।

इस पूरे विवाद की जड़ें साल 2010 से जुड़ी हैं, जब राज्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार और उसके बाद सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने राज्य के भीतर एक ऐसा सामाजिक समीकरण तैयार करने की कोशिश की, जो चुनावी राजनीति में अजेय किला बन सके। ममता बनर्जी के कार्यकाल के दौरान पिछड़ा वर्ग सूची में 140 से ज्यादा नई उप-जातियों को जोड़ा गया था, जिनमें से करीब 80 फीसदी जातियां केवल एक विशेष समुदाय से थीं। आंकड़ों की बाजीगरी ऐसी थी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में रहने वाले करीब ढाई करोड़ मुसलमानों में से दो करोड़ से अधिक लोगों को कागजों पर रातों-रात 'ओबीसी' घोषित कर दिया गया। अत्यंत पिछड़ों के लिए बनी 'ओबीसी-ए' कैटेगरी में बड़े पैमाने पर मुस्लिम उप-जातियों को जगह मिलने का सीधा नतीजा यह हुआ कि नौकरियों और सरकारी शिक्षा संस्थानों में मिलने वाले कोटे पर एक खास वर्ग का वर्चस्व स्थापित होने लगा। इस पूरी प्रक्रिया ने उन मूल हिंदू पिछड़ी जातियों को हाशिए पर धकेल दिया, जो पीढ़ियों से अपने हक का इंतजार कर रही थीं। माहिष्य, सद्गोप, यादव और कुर्मी जैसी बड़ी पिछड़ी जातियां हों या फिर चुनिया और कलवार जैसे छोटे शिल्पी वर्ग, वे सभी संख्याबल और इस नए मुकाबले में पीछे छूटते चले गए।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब इस पूरे मामले की परतें खोलीं, तो यह स्पष्ट हो गया कि बिना किसी व्यापक सर्वेक्षण या पिछड़ेपन के वैज्ञानिक मूल्यांकन के पूरी की पूरी आबादी को आरक्षण के दायरे में लाना संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। अदालत के इसी फैसले को आधार बनाकर सुवेंदु सरकार ने 2012 के बाद की व्यवस्था को पूरी तरह रद कर 2010 की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है, जिसके तहत केवल 66 जातियां ही वैध रूप से ओबीसी कोटे की हकदार मानी गई हैं। इस सूची में कपाली, कुर्मी, नाई (नापित), तांती, धानुक, कसाई, खंडैत, तुरहा, पहाड़िया मुस्लिम, देवांगा और हज्जाम जैसी पारंपरिक जातियों को शामिल किया गया है। साथ ही, अनुसूचित जाति से ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्तियों को भी इस सूची में स्थान मिला है। सरकार का अगला कदम और भी आक्रामक है, जिसके तहत 2011 के बाद से जारी किए गए सभी 1.69 करोड़ जाति प्रमाणपत्रों की व्यापक स्तर पर दोबारा जांच (री-वेरिफिकेशन) के आदेश दिए गए हैं। इसमें विशेष रूप से उन प्रमाण पत्रों को खंगाला जाएगा जो 'द्वारे सरकार' जैसे लोक-लुभावन कैंपों के जरिए आनन-फानन में बांटे गए थे।

यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई अन्य सूबों में भी 'मजहब आधारित आरक्षण' बनाम 'संवैधानिक मयार्दा' की इस बहस को नए सिरे से जिंदा करता है। कर्नाटक में 1990 के दशक में मुस्लिमों के लिए ओबीसी सूची के तहत जो 4 फीसदी का सब-कोटा तय किया गया था, उसे मार्च 2023 में तत्कालीन सरकार ने असंवैधानिक बताते हुए खत्म कर दिया और मामला अब शीर्ष अदालत के विचाराधीन है। केरल में 1952 से ही लगभग पूरी मुस्लिम आबादी को पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल रहा है, जहां हिंदू पिछड़ी जातियां लगातार आरोप लगाती रही हैं कि कोटे का बड़ा हिस्सा एक खास संपन्न वर्ग हड़प लेता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी पूरी आबादी को एकमुश्त आरक्षण देने के प्रयासों को अदालतों ने हमेशा खारिज किया है, जिसके बाद चुनिंदा जातियों को पहचान कर अलग कैटेगरी बनाई गई। इसके विपरीत बिहार जैसे राज्य में मंडल आयोग की सिफारिशों के तहत केवल पेशेवर और सामाजिक रूप से पिछड़ी मुस्लिम जातियों (जैसे अंसारी और कुरैशी) को ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) में रखा गया है। यह तुलना दिखाती है कि जब भी राज्य सरकारों ने वैज्ञानिक डेटा को दरकिनार कर केवल राजनीतिक लाभ के लिए एकमुश्त समुदायों को पिछड़ेपन का तमगा दिया, वहां कानूनी और सामाजिक टकराव होना तय था। संविधान का अनुच्छेद 16(2) स्पष्ट रूप से धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या आरक्षण को प्रतिबंधित करता है, जबकि अनुच्छेद 15(4) केवल सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को ही आरक्षण का वैध आधार मानता है। 1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने यह साफ कर दिया था कि गैर-हिंदू जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए उनका सामाजिक पिछड़ापन एक वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध होना अनिवार्य है। बंगाल में इसी संवैधानिक मयार्दा को ताक पर रखने का आरोप विपक्ष पर लगता रहा है, जहां मुस्लिम वोटबैंक को साधने के लिए जातियों के आंतरिक ढांचे की अनदेखी की गई। राजनीति की इस बिसात पर दोनों पक्षों के नियम एक-दूसरे से पूरी तरह उलट हैं। एक तरफ जहां बहुसंख्यक समाज को एकजुट रखने और 'सनातनी पहचान' के तहत क्षेत्रीय दलों के जातीय कार्ड को बेअसर करने की रणनीति चलती है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के भीतर की उस परत को खोलने का प्रयास हो रहा है जिसे मुख्यधारा की सेक्युलर राजनीति ने हमेशा छिपाकर रखा यानी 'अशराफ बनाम पसमांदा' का भेद। समाज के ऊंचे तबके (सैयद, शेख, पठान) ने हमेशा राजनीतिक और सामाजिक मलाई का आनंद लिया, जबकि जुलाहे, कसाई और बुनकर जैसे गरीब पिछड़े मुस्लिम समाज के हाशिए पर ही रहे। इसके विपरीत, क्षेत्रीय दलों का पूरा वजूद ही इस बात पर टिका है कि बहुसंख्यक समाज अपनी जातियों के छोटे-छोटे ब्लॉकों में बंटा रहे, ताकि 'जितनी आबादी, उतना हक' का नैरेटिव सेट किया जा सके। लेकिन जब बात अल्पसंख्यक समाज की आती है, तो यही दल कभी नहीं चाहते कि वह जातियों या अशराफ-पसमांदा के भेद में बंटे। वहां कोशिश यही होती है कि आंतरिक अंतर्विरोधों के बावजूद वे एक 'धार्मिक पहचान' के तहत एकमुश्त वोटबैंक बने रहें। इस्लामी धर्मशास्त्र के मुताबिक सैद्धांतिक तौर पर इस्लाम में ऊंच-नीच या जाति व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है, और यही तर्क अक्सर आरक्षण के विरोध या समर्थन में धार्मिक मोड़ ले लेता है। लेकिन समाजशास्त्रियों का मानना है कि दक्षिण एशिया और खासकर भारत में, जिन जातियों का धर्मांतरण हुआ, वे अपनी धार्मिक पहचान बदलने के बाद भी अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जातिगत पहचान को नहीं छोड़ पाईं।

पत्रकार चंद्रकांत दुबे की मां नगीना देवी का निधन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। 'दोपहर का सामना' के वरिष्ठ पत्रकार चंद्रकांत दुबे की मां स्वरूप चाची नगीना देवी शिव प्रसाद दुबे (८५) का अकस्मात हृदयगति के रुक जाने से १८ मई को निधन हो गया। वे मुंबई से लेकर गांव तक समाज सेवा में समर्पित रही। उनका अंतिम संस्कार भायंदर पूर्व स्थित बंदरवाड़ी श्मशान में हुआ, जहां उनके बड़े बेटे दिवाकर प्रसाद दुबे ने मुखाग्नि दी और छोटे बेटे अरुण दुबे समाजसेवा से जुड़े हैं। बाकी सभी कार्यक्रम पैतृक गांव-दौलतपुर, खुटहन, जिला जौनपुर में किया जायेगा। नगीना देवी अत्यंत दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वे अपने पीछे जवाहर लाल दुबे, डॉ.विपीन दुबे, सुनील, मनोज, प्रभाकर, सुधाकर, कृष्णकांत, वशिष्ठ, ईशानारायण, शेष नारायण, महेश नारायण, रामानंद (डीएम),चिराग, सिद्धार्थ, अनुराग आदि से भरा पूरा परिवार छोड़ गई।

भिवंडी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आरटीआई संगठन द्वारा जनसेवा शिविर के आयोजन में असंख्य लोगों ने उठाया लाभ

भिवंडी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आरटीआई संगठन कमेटी भिवंडी की ओर से पहली बार जनसेवा शिविर का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज चौक स्थित किया गया। इस शिविर के माध्यम से आधार कार्ड सुधार, पैन कार्ड सेवा, विधवा पेंशन योजना, आयुष्मान कार्ड तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी और मार्गदर्शन नागरिकों को प्रदान किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रमुख अतिथियों के रूप में पूर्व महापौर विलास आर. पाटिल, पूर्व महापौर प्रतिभा विलास पाटिल, नगरसेवक एडवोकेट मयुरेश विलास पाटिल तथा नगरसेविका नेहा नवीन पाठक के शुभहस्तों से संपन्न हुआ। बतादें कि यह जनसेवा शिविर कार्यक्रम राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी भिवंडी शहर और कोणार्क विकास आघाडी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लेकर विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की और सेवाओं का लाभ उठाया। कार्यक्रम को सफल बनाने में उपाध्यक्ष रमेश आर. भैरी, हरीश अग्रवाल, शरद जाधव, श्रीनिवास मंगल पिल्ली, धनराज गायकवाड, विजय उप्पल पेवार, कोषाध्यक्ष दल प्रताप सिंह तथा संगठन मंत्री आप्पा शिंदे सहित अनेक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विशेष योगदान दिया।

इंडो नेशनल लिमिटेड ने लॉन्च की 'Nippo THOR Max'

मुंबई। इंडो नेशनल लिमिटेड ने, जो प्रतिष्ठित उपभोक्ता ब्रांड Nippo के पीछे की कंपनी है, आज अपनी सबसे उन्नत अल्कलाइन बैटरी Nippo THOR Max लॉन्च करने की घोषणा की। इस लॉन्च के साथ कंपनी ने प्रीमियम बैटरी सेगमेंट में एक महत्वपूर्ण कदम रखा है। अत्याधुनिक KOH तकनीक से तैयार की गई Nippo THOR Max को गेमिंग कंट्रोलर्स, खिलौनों, स्मार्ट होम डिवाइसेस और वायरलेस एक्सेसरीज जैसे हाई-ड्रेन डिवाइसेस के लिए डिजाइन किया गया है। दमदार पावर, लंबी चलने वाली क्षमता और भरोसेमंद प्रदर्शन के कारण इस उत्पाद को भारत की सबसे शक्तिशाली अल्कलाइन बैटरी के रूप में पेश किया गया है। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब प्रीमियम अल्कलाइन बैटरी सेगमेंट, जो वर्तमान में अल्कलाइन कैटेगरी के लगभग 20% व्यवसाय का हिस्सा है, लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। बैटरी पर अधिक निर्भर आधुनिक उपकरणों के बढ़ते उपयोग और बेहतर प्रदर्शन वाले उत्पादों की उपभोक्ता मांग इस ग्रोथ को आगे बढ़ा रही है। कंपनी की आंतरिक लैब टेस्टिंग के अनुसार, Nippo THOR Max हाई-ड्रेन डिवाइसेस में प्रतिस्पर्धी ब्रांड्स की तुलना में 20% से अधिक लंबा प्रदर्शन देती है। इसके साथ ही इसमें 10 वर्षों की शेल्फ लाइफ भी दी गई है, जो इसे उपभोक्ताओं के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। प्रीमियम लैमिनेटेड पैकेजिंग इसकी शेल्फ अपील और ग्राहक अनुभव को और बेहतर बनाती है। इस लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए पवन कुमार बीवीएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इंडो नेशनल लिमिटेड ने कहा, "Nippo THOR Max का लॉन्च बदलते बैटरी बाजार में हमारी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दांतों की सफाई में लापरवाही, पड़ सकती है बहुत भारी : डॉ. सोनिया दत्ता

मुंबई/पटना। प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. सोनिया दत्ता द्वारा विशेष ओरल हेल्थ विश्लेषण से पता चलता है की अक्सर लोग दांतों के डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब दर्द असहनीय हो जाता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे एक बड़ी गलती मानते हैं। दांतों की अधिकांश समस्याएं, जैसे कैविटी और मसूड़ों की बीमारी, बिना किसी दर्द के शुरू होती हैं। इसी वजह से लोग हल्की सफाई और देखभाल को नजरअंदाज करते रहते हैं। यह लापरवाही मामूली समस्या को भविष्य में एक गंभीर और बड़े नुकसान में बदल देती है, जिसका पता अक्सर तब चलता है जब स्थिति काफी बिगड़ चुकी होती है। लापरवाही का यह सिलसिला तब शुरू होता है जब हम रोजाना ठीक से दांत साफ नहीं करते। दांतों पर जमने वाली परत (प्लाक) कुछ ही दिनों में सख्त होकर 'टार्टर' बन जाती है, जिसे साधारण ब्रशिंग से नहीं हटाया जा सकता। यही टार्टर मसूड़ों में सूजन और दांतों की सड़न का मुख्य कारण बनता है।

कैंपस एक्टिववियर ने युवा सोच, व्यक्तित्व और गतिशील जीवनशैली को दर्शाती अपनी नई ब्राण्ड पहचान पेश की

मुंबई/पटना। भारत के अग्रणी स्पोर्ट्स और एथलीजर ब्राण्ड्स में शामिल कैंपस एक्टिववियर लिमिटेड ने अपनी वार्षिक डिस्ट्रीब्यूटर्स मीट शूकेस 2026 के दौरान ब्राण्ड की नई पहचान पेश की। यह बदलाव केवल लोगो या डिजाइन तक सीमित नहीं है, बल्कि कैंपस की विकास यात्रा के अगले चरण का संकेत है। नई पहचान कैंपस को एक ऐसे ब्राण्ड के रूप में सामने लाती है जो आज की युवा पीढ़ी की सोच, उसकी जीवनशैली और आत्मअभिव्यक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ है। इस नई पहचान के केंद्र में बाहर की ओर बढ़ते तीन तीर हैं, जो अलग अलग दिशाओं, विकल्पों और संभावनाओं का प्रतीक हैं। यह इस विचार को दर्शाते हैं कि आगे बढ़ने या अपनी पहचान बनाने का कोई एक तय रास्ता नहीं होता। ह्यूमन योर वेब की सोच पर आधारित यह नई पहचान हर व्यक्ति को अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने की आजादी को अभिव्यक्त करती है। वैश्विक दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई यह पहचान भारतीय युवाओं की मानसिकता और जीवन दृष्टि से भी जुड़ी हुई है। यह उस पीढ़ी की सोच को सामने लाती है जो मौलिकता, आत्मविश्वास और अपनी राह खुद चुनने की स्वतंत्रता को महत्व देती है। साथ ही यह कैंपस के उस बदलाव को भी दर्शाती है जहाँ फैशन, खेल और रोजमर्रा की जीवनशैली एक दूसरे से सहज रूप से जुड़ते हैं। नई पहचान का अनावरण कैंपस की वार्षिक डिस्ट्रीब्यूटर्स मीट शूकेस 2026 के दौरान किया गया। तीन दिनों तक चले इस आयोजन में देशभर से 300 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर पार्टनर्स शामिल हुए।

हिंदू समुदाय पर अन्याय करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा : कैबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा

मुंबई (उत्तरशक्ति)। मालवणी क्षेत्र में स्थानीय नगरसेवक और विधायक के संरक्षण में अवैध निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा स्थानीय लोगों पर दबाव बनाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को आश्रय दिया जा रहा है, ऐसा आरोप कैबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने लगाया है। भू-माफिया और अवैध निर्माण करने वाले हिंदू समुदाय पर अन्याय कर रहे हैं और अब यह अन्याय किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा, ऐसा मंत्री लोढ़ा ने स्पष्ट किया। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और इनके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।

मालवणी क्षेत्र स्थित सावरिया मस्जिद परिसर में रहने वाली रागिनी रामाशंकर चौरसिया नामक महिला के घर का दरवाजा बंद कर अवैध निर्माण किया गया है। पीड़ित महिला से मुलाकात करने के बाद मंत्री लोढ़ा पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

मालवणी के अब्बासिया कंपाउंड में रहने वाली रागिनी रामाशंकर चौरसिया के घर से सटे क्षेत्र में शौकत हुसैन आबिद हुसैन सैय्यद द्वारा अवैध निर्माण किया

गया। इतना ही नहीं, चौरसिया परिवार को घर का दरवाजा बंद करने के लिए मजबूर किया गया। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन आबिद और हुसैन ने इसे नजरअंदाज करते हुए निर्माण को वैध बताया। हालांकि मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि निर्माण अवैध है। कैबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पीड़ित महिला से मुलाकात की तथा मालवणी पुलिस थाने में वरिष्ठ अधिकारियों से कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार किया है।

वहीं राज्य में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में गृह विभाग प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है। राज्य में हिंदू समुदाय पर अत्याचार किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और आरोपियों पर ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि भविष्य में कोई भी हिंदू समाज पर अन्याय करने का साहस नहीं करेगा, ऐसा चेतावनी स्वरूप वक्तव्य मंत्री लोढ़ा ने दिया। स्थानीय विधायक असलम शेख के नगरसेवक पुत्र ने अब्बासिया कंपाउंड में सड़क पर अवैध छबील (प्याऊ) निर्माण का उद्घाटन किया था। बिना किसी अनुमति के 6 फुट बाय 12 फुट क्षेत्रफल का सीमेंट और ईंटों का निर्माण लगभग 14 फुट ऊंचाई तक किया गया है। इसके लिए 6 लोहे के खंभे भी लगाए गए हैं। इस मामले में अब महानगरपालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है तथा अवैध निर्माण करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, ऐसी जानकारी पुलिस ने दी है।

समरस फाउंडेशन ने किया सीमा पर तैनात सैनिक विकास यादव का सम्मान

मुंबई (उत्तरशक्ति)। महानगर की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था समरस फाउंडेशन द्वारा आज बोरीवली पूर्व स्थित कार्यालय में जम्मू में पाक सीमा पर तैनात सैनिक विकास यादव का सम्मान किया। संस्था के चेयरमैन डॉ किशोर सिंह ने शॉल और पुष्पगुच्छ से उनका सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सैनिकों के कारण ही हम भारतवासी चैन की नींद सो रहे हैं। विकट परिस्थितियों में भी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के कारण ही देश सुरक्षित है। इस अवसर पर समाजसेवी रामकृपाल शर्मा, समाजसेवी सुग्रीव यादव, संस्था के महासचिव वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे, उपाध्यक्ष मुकुंद शर्मा, उपाध्यक्ष मानिकचंद यादव, विधि सलाहकार एड. प्रशांत परदेसी, रामलिंगम, रामचंद्रन, पूरव गांधी, किरीट बावरिया समेत अनेक गणमान्य उपस्थित रहे।

रील्स का नशा समाज पे गहरा प्रभाव

निक्की शर्मा रश्मि

मुम्बई (उत्तरशक्ति)। समाज आज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो वह है सोशल मीडिया। सस्ती लोकप्रियता कमाने की होड़ जो आज सबसे गंभीर बीमारी बन गई है अच्छे अच्छे लोग उसके नशे में आ रहे हैं। जी हां नशा... यह नशा ही तो हो गया है। सस्ती लोकप्रियता कमाने का छोटे-छोटे कपड़े पहनकर नाचना अपने घरों की बातें लड़ाई झगड़ा जानबूझकर दिखाना। चंद पैसों के लिए कहां तक उचित है ? टैलेंट है तो जरूर दिखानी चाहिए लेकिन आज कम कपड़ों में गाली-गलौज के साथ जो लोग अश्लीलता फैला कर समाज को दूषित कर रहे हैं वह भूल रहे हैं कल समाज उनके बच्चों को क्या देगा झूठी शान दिखावटी रिश्ते। युवा पीढ़ी की मानसिकता और सामाजिक मूल्यों पर काफी प्रभाव डालती है। रील्स का प्रभाव परंपरा और वास्तविक जीवन को खत्म कर रही है। स्टारडम और पैसे कमाने की होड़ में लोग अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं। रील्स कितनी घातक हो रही समाज के लिए इसका असर काफी हद तक देखने को मिल रहा। सभ्यता, मयार्दा को ताक पर रखकर रील्स बनाकर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं या नहीं यह उन्हें खुद सोचना चाहिए। कितने रिश्ते दूर हो रहे... टूट रहे इस रील्स के चक्कर में। इस रील्स को छोड़ना आसान नहीं होगा रील्स ने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया लेकिन लोग अश्लीलता फैला कर गलत संदेश दे रहे। डांस, एक्टिंग, कुकिंग, पेंटिंग जैसे विषयों पर लोगों ने कंटेंट डालकर समाज को एक नई दिशा दी है। अच्छे रिल्स बनाकर बहुत कामयाब हुए। वहीं घटिया रील्स ने कई घरों को बर्बाद किया और कर रहे हैं। समाज छोटे-छोटे बच्चों से गाली गलौज करवा कर रील्स बनाकर समाज में परोस रहे हैं। किस ओर जा रहा हमारा समाज ऐसे रिल्स को मिलियन व्यूज जाते हैं। देखने वाले भी इसी समाज के हैं वह भूल रहे हैं क्या परोसा जा रहा और हम क्या देख रहे हैं। अच्छे कंटेंट ने बहुत युवाओं को केरियर दिया है वहीं घटिया कंटेंट समाज पर असर डाल रहे हैं। केवल पैसे कमाने के लिए गंदे कंटेंट डाल रहे। परिवार के साथ समय बिताने के बजाय रील्स देखने में बिजी हैं। आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं... दूरियां आ रही। विवादित कंटेंट समाज में नकारात्मकता फैला रही है ।वहीं दिमाग में असर डाल रहे हैं। वही लोग नकल भी करने लगे हैं। बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है ।गंदे कंटेंट मानसिक स्वास्थ्य और समाज के लिए घातक है। जल्द ही लगाम लगाने की आवश्यकता है। धैर्य खोता जा रहा है समाज। पैसे और सस्ती लोकप्रियता में लोग कुछ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत न्यूज तुरंत फैल जाती है वहीं अच्छे न्यूज पर व्यूज कम जाते हैं। समाज में तनाव और गलत धारणाएं पैदा हो रही है। मानवीय संवेदनाएं कमजोर हो रही हैं। वास्तविक संबंध खराब हो रहे हैं। आपसी लगाव धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। समाज में गंदगी फैल रही है साथ ही आपसी रिश्ते मजबूत होने की बजाय टूट रहे हैं। गंदे कंटेंट पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है जिससे समाज को अच्छा संदेश जाए और अच्छे लोग जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं वह अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचे। मयार्दा, परंपरा के साथ एक अच्छा समाज देना हमारा दायित्व है ..आगे आने वाली पीढ़ी को। आगे आने वाली पीढ़ी जो देखेगी वही सीखेगी हमारा दायित्व है उन्हें अच्छे कंटेंट परोसा जाए और गंदे कंटेंट पर लगाम लगाई जाए ।कंटेंट बनाना है तो मयार्दा और संस्कार में रहकर बनानी चाहिए साथ ही समाज को नयी दिशा दे ऐसी सोच रखनी चाहिए ।अच्छे कंटेंट बनाकर यूवा अपना केरीयर बनायें ना की गंदे कंटेंट बनाकर रिश्तों की मयार्दा को खत्म करें ।परिवार ही सबकुछ है उनकी मयार्दा और संस्कार का ख्याल रखकर अपने शौक को पूरे करें।

कदम कृष्णा मेडिकल सहायता कक्ष को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार घोषित

मुंबई (उत्तरशक्ति)। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद मरीजों को समय पर उपचार, अस्पताल में बेड, रक्त एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पिछले छह वर्षों से लगातार कार्यरत कदम कृष्णा मेडिकल सहायता कक्ष को इस वर्ष का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया है। सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए रोगी सेवा के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा मारुति कदम ने कोरोना काल की भयावह परिस्थितियों के दौरान अनेक मरीजों को उपचार के लिए होने वाली परेशानियों को करीब से

देखा था। इसके बाद जरूरतमंद नागरिकों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कदम कृष्णा मेडिकल सहायता कक्ष की स्थापना की गई। बहुत ही कम समय में इस कक्ष ने हजारों मरीजों को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराकर समाज में अपनी विश्वसनीय पहचान बनाई है। रविवार, 24 मई 2026 को गोवा स्थित हिल्टन होटल में आयोजित विशेष समारोह में संस्था को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले भी संस्था के सामाजिक एवं चिकित्सा क्षेत्र में किए गए कार्यों को देखते हुए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर प्रतिक्रिया देते हुए संस्था के अध्यक्ष कृष्णा कदम ने कहा कि यह पुरस्कार केवल मेरा नहीं, बल्कि संस्था में ईमानदारी और निस्वार्थ भावना से कार्य करने वाले प्रत्येक सदस्य का है। रोगी सेवा का यह कार्य भविष्य में भी और अधिक उत्साह के साथ जारी रखा जाएगा।

भिवंडी मनपा ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाकर किया जमींदोज, अवैध बांधकाम करने वालों में खलबली

भिवंडी (उत्तरशक्ति)। भिवंडी मनपा प्रभाग समिति 3 के अंतर्गत शास्त्री नगर इलाके में लगातार दो दिनों से बुलडोजर और हथौड़ा से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बतादें कि भिवंडी मनपा के आयुक्त अनमोल सागर, अतिरिक्त आयुक्त विट्ठल डाके और उपायुक्त विक्रम दराडे के आदेश पर प्रभाग समिति 3 के सहायक आयुक्त सुरेंद्र भोईर और उनकी अतिक्रमण टीम ने शास्त्री नगर में अवैध निमार्णों पर बड़ा एक्शन लिया। जानकारी के अनुसार शास्त्री नगर वार्ड नंबर 3 स्थित घर नंबर 646 के ग्राउंड फ्लोर पर बिना परमिशन निर्माण की सूचना मिलते ही सुरेंद्र भोईर और टीम मौके पर पहुंची और हथौड़ा व अन्य

उपकरणों से तोड़क कार्रवाई कर दी। इस दौरान सहायक आयुक्त सुरेंद्र भोईर ने साफ चेतावनी दी कि भिवंडी में बिना अनुमति कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे निमार्णों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इसी क्रम में 19/05/2026 को वार्ड नंबर 3 के मकान नंबर 664 पर अवैध रूप से किए गए फ्छउ कॉलम निर्माण पर भी भारी कार्रवाई की गई। टीम ने सुरेंद्र भोईर की उपस्थिति में खउइ बुलडोजर की मदद से निर्माण को जमींदोज कर दिया।अब शास्त्री नगर में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। बिल्डरों में डर का माहौल है और पूरे इलाके में चर्चा है कि भिवंडी मनपा का बुलडोजर एक्शन पूरी ताकत के साथ शुरू हो चुका है। भिवंडी में अवैध निर्माण करने वालों के लिए यह साफ संदेश है कि अब कानून का हथौड़ा और बुलडोजर दोनों चलेगा।

किआ इंडिया की टेनिस प्रीमियर लीग के साथ साझेदारी

मुंबई। किआ इंडिया और टेनिस प्रीमियर लीग (टीपीएल) ने आज तीन साल की एक बड़ी साझेदारी का ऐलान किया है, जिसके तहत किआ इंडिया लीग की एक्सक्लूसिव स्पॉन्सर बनी है। टेनिस के साथ किआ इंडिया के लंबे समय से चले आ रहे वैश्विक जुड़ाव और भारत में इस खेल के लिए टीपीएल के बढ़ते इकोसिस्टम को एक साथ लाते हुए, यह साझेदारी एक साझा सोच को दर्शाती है जो टेनिस की अहमियत और पहुंच को मजबूत करने और देशभर में दर्शकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करने की बात करती है।

इस बहु-वर्षीय साझेदारी के तहत किआ इंडिया टेनिस प्रीमियर लीग के पूरे इकोसिस्टम में शामिल होगी, जिसमें टीपीएल ऐप और सभी आठ फ्रेंचाइजी टीमें भी शामिल हैं। किआ इंडिया इन सभी टीमों की फ्रंट-ऑफ-जर्सी स्पॉन्सर होगी। यह साझेदारी टेनिस के आसपास ज्यादा भागीदारी और जुड़ाव बढ़ाने की किआ इंडिया की सोच से भी मेल खाती है और साथ ही टीपीएल की जमीनी स्तर की पहलों को और मजबूत करेगी, जिन्होंने देशभर में टूर्नामेंट कराने और उभरती टेनिस प्रतिभाओं को पहचानने में अहम भूमिका निभाई है।

पिछले दो सालों में टीपीएल ने अपनी प्रमुख ‘रेस टू गोल्ड स्कॉलरशिप’ पहल के जरिए भारत भर के 80 से ज्यादा युवा टेनिस खिलाड़ियों को सहयोग दिया है। किआ इंडिया के साथ आने से अब यह सोच और आगे बढ़ेगी। आने वाले सालों में 120 से ज्यादा और युवा खिलाड़ियों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है, ताकि लंबे समय में ऐसे ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकें जो 2036 ओलंपिक में देश के लिए पदक जीत सकें।

किआ इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग अतुल सूद ने कहा, ‘किआ इंडिया में हमारा मानना है कि खेलों में लोगों की आकांक्षाओं को प्रेरित करने और सार्थक सांस्कृतिक जुड़ाव बनाने की ताकत होती है। टेनिस में जो युवा ऊर्जा, वैश्विक अपील और प्रीमियम पहचान है वह हमारी ब्रांड फिलॉसफी से बहुत अच्छी तरह मेल खाती है। टेनिस प्रीमियर लीग के साथ हमारी यह साझेदारी भारत में नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए टेनिस को और दिलचस्प और प्रासंगिक बनाने की साझा सोच को दर्शाती है। टीपीएल के बढ़ते इकोसिस्टम और जमीनी स्तर पर इसके फोकस के जरिए हम इस खेल में ज्यादा भागीदारी, जुड़ाव और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद रखते हैं।

टेनिस प्रीमियर लीग के को-फाउंडर कुणाल ठक्कर ने कहा, ‘किआ इंडिया के साथ यह साझेदारी हमारे लिए एक बहुत खास पल है। पिछले कुछ सालों में हमने अपने ऐप और रेस टू गोल्ड जैसी पहलों के साथ लीग के जरिए एक मजबूत जमीनी इकोसिस्टम बनाने पर काफी ध्यान दिया है। किआ इंडिया जैसे वैश्विक ब्रांड का इस सोच को पहचानना और उसका साथ देना हमें अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने का भरोसा देता है और भारतीय टेनिस के भविष्य पर सच में असर डालने की ताकत देता है। टेनिस प्रीमियर लीग के को-फाउंडर मृणाल जैन ने कहा, ‘टीपीएल हमेशा से एक पूरा टेनिस इकोसिस्टम बनाने में विश्वास रखता आया है, जिसमें युवा प्रतिभाओं की पहचान से लेकर उन्हें सबसे बड़े मंच तक पहुंचाना शामिल है। किआ इंडिया के साथ जुड़कर हमें सिर्फ एक स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, बल्कि एक ऐसा लंबे समय का साथी भी मिला है जो भारत के लिए चैंपियन तैयार करने के हमारे विजन से पूरी तरह सहमत है। 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन लिएंडर पेस ने कहा, ‘सालों से टेनिस प्रीमियर लीग ने एक मजबूत मंच बनाया है जो टेनिस को हर स्तर पर बढ़ाने में मदद कर रहा है, जमीनी विकास से लेकर पेशेवर मुकाबलों तक।

किआ इंडिया के साथ इस तरह की साझेदारियां भारतीय टेनिस के भविष्य के लिए बेहद अहम हैं, क्योंकि वे इकोसिस्टम को लंबे समय का विजन, विश्वसनीयता और मायने रखने वाला सहयोग देती हैं।

मुंबई के हर्ष पटेल को भारत सरकार की दूरसंचार समिति के सदस्य के रूप में नामांकन

मुंबई। एक ऐसा लड़का जो मुंबई की गलियों में पला-बढ़ा, जिसके पिता मझोले दर्जे के नौकरीपेशा व्यक्ति थे और माता गृहिणी। जिसकी शिक्षा-यात्रा नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स और गोपालदास झमतमल अडवाणी लॉ कॉलेज से होकर गुजरी। आज उसी लड़के का भारत सरकार के संचार मंत्रालय की दूरसंचार सलाहकार समिति (टेलिकॉम एडवाइजरी कमेटी) के सदस्य के रूप में नामांकन एक ऐतिहासिक 'वापसी' जैसा है।

एडवोकेट सीए. हर्ष गिरीश पटेल, जो वाटर एंड शार्क के संस्थापक और वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्लोबल सीईओ) हैं, को उनकी विशिष्ट कानूनी विशेषज्ञता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेतृत्व और वैश्विक शासन ढाँचों में भारत की स्थिति को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए इस उच्चस्तरीय समिति में नामित किया गया है। श्री पटेल की शैक्षिक यात्रा पूरी तरह से मुंबई की धरती से जुड़ी हुई है। उन्होंने नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम) और गोपालदास झमतमल अडवाणी लॉ कॉलेज से कानून की स्नातक (एल.एल.बी.) की उपाधि प्राप्त की। वह भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) से चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) भी हैं।

इसके अलावा, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कंब्रिया से कानून में स्नातकोत्तर (एल.एल.एम.) किया है। वह सीपीए ऑस्ट्रेलिया और इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स (यूके) के फेलो सदस्य हैं, तथा यूके की सॉलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी (एसआरए) में पंजीकृत विदेशी वकील भी हैं। श्री पटेल ने कहा, ‘मुंबई में बड़ा होकर मैंने दो चीजें सीखीं: महत्वाकांक्षा और संघर्ष की ताकत। मुंबई आपको सफलता उपहार में नहीं देती, बल्कि आपको चुनौती देती है कि आप उसे कमाएँ। नरसी मोनजी की कक्षाओं से लेकर यूरोपीय संसद के गलियारों तक, और जी.जे. अडवाणी लॉ कॉलेज से ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक – हर कदम पर उन मूल्यों ने मार्गदर्शन किया, जो मैंने इस शहर से सीखे।

मात्र १९ वर्ष की आयु में, जब वह अभी सीए की पढ़ाई कर ही रहे थे, हर्ष पटेल ने मुंबई में एक किराए की मेज से 'वाटर एंड शार्क' की नींव रखी थी। आज यह फर्म १२ से अधिक देशों में कार्यरत है।

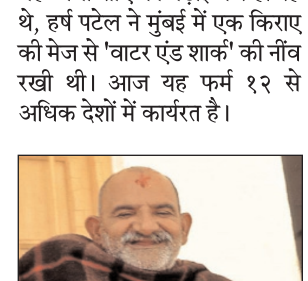

नीम करौली बाबा

उत्तरशक्ति
* संपादकः ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादकः प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादकः डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल ऑटाफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

स्वामीः शरद फागूराम प्रजापति, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति द्वारा सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, यूनिट क्रमांक 4, तल मजला, एन.के. इंडस्ट्रियल स्टेट, आरे रोड, प्रवासी इंडस्ट्रियल एस्टेट, जवल, गेट क्रमांक 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063, महाराष्ट्र से मुदित एवं के-4, रूम नं. 8, ग्राउंड फ्लोर न्यू समता सहकारी को.ऑ. हां. सोसाइटी, एमएमआरडीए कॉलोनी कंजूरमार्ग (वेस्ट), जिला मुंबई- 400078, महाराष्ट्र से प्रकाशित। RNI NO. MAHHIN/2018/76092 * **संपादक- ओमप्रकाश रविंद्रनाथ प्रजापति,** समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त समाचारों के लिए उत्तरदाई तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद मुंबई न्यायालय के अधीन होंगे।
पत्राचार कार्यालयः मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5 ए-337 ट्रैक टर्मिनल, डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जवल, ऑटाफ हिल, वडाला मुंबई -37, **मो.-** 9554493941 **email ID- uttarshaktinews@gmail.com**

गाय बने राष्ट्रीय पशु, बैल उद्योग को मिले वैध दर्जा

मोहम्मद अरशद खान ने पीएम मोदी को भेजा बड़ा प्रस्ताव

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक जौनपुर सदर मोहम्मद अरशद खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर देश की पशुधन नीति में बड़े बदलाव की मांग उठाई है। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और पूरे देश में गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

जौनपुर स्थित पीडीए भवन, कटघरा से जारी प्रेस रिलीज में मोहम्मद अरशद खान ने कहा कि देश में करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए गाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि तत्कालीन बादशाह हुमायूं की नीति की तरह पूरे देश में गाय काटने पर प्रतिबंध लागू किया जाए।

इसके साथ ही उन्होंने बैल काटने पर लगी पाबंदियां हटाने तथा बैल आधारित उद्योग को वैधानिक

और आर्थिक संरक्षण देने की मांग की। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में अनुपयोगी पशुओं का भार गरीब किसानों पर पड़ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है।

उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि जो गाय दूध देना और बच्चा पैदा करना बंद कर दे, उन्हें भाजपा नेताओं के संरक्षण में देने की राष्ट्रीय योजना बनाई जाए, ताकि गोसेवा के दावों की वास्तविक परीक्षा हो सके और किसानों को राहत मिले।

मोहम्मद अरशद खान ने दावा किया कि बैल आधारित मांस निर्यात उद्योग को कानूनी औद्योगिक दर्जा मिलने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा और करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे किसानों, पशुपालकों और निर्यात क्षेत्र को नई आर्थिक ताकत मिलेगी।

उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि भावनात्मक राजनीति के बजाय वैज्ञानिक, संवैधानिक और आर्थिक दृष्टिकोण अपनाकर नई पशुधन नीति बनाई जाए, जिससे कृषि, पशुपालन, डेयरी और निर्यात क्षेत्र को मजबूती मिल सके।

भाजपा प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाने की तैयारियां तेज

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। भारतीय जनता पार्टी के आगामी प्रशिक्षण वर्ग को ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से भाजपा जिला कार्यालय जौनपुर में जिला पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष अजित प्रजापति ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष एवं वर्ग संचालन समिति प्रमुख सुशील उपाध्याय मौजूद रहे।

बैठक की शुरुआत भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण एवं वंदे मातरम के साथ हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि भाजपा एक कैडर आधारित संगठन है, जहां प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के वैचारिक और सांगठनिक विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि वर्ग की

जिला पदाधिकारियों की अहम बैठक संपन्न

सफलता के लिए पूर्व तैयारियां मजबूत होना जरूरी है और सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ताओं को पार्टी के इतिहास, विचारधारा, राष्ट्रवाद, अंत्योदय और सामाजिक सरोकारों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही तकनीकी और सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय

ने कहा कि भाजपा में व्यक्ति नहीं बल्कि विचार नीति तय करता है। प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एकात्म मानववाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ने का कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है।

जिला मीडिया प्रभारी आमोद सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग के सफल संचालन के लिए भोजन, आवास, सुरक्षा, पार्किंग, पंजीकरण, मंच व्यवस्था और साज-सज्जा को लेकर अलग-अलग समितियों का गठन किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों के मोबाइल जमा कराने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि सभी कार्यकर्ता एकाग्र होकर सत्रों में भाग ले सकें।

बैठक के अंत में जिला महामंत्री अजय सिंह ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षण वर्ग को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। बैठक में भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में धूमधाम से मनाया गया उर्दू शिक्षिका रहीमा खातून का जन्मदिवस

डॉ.इम्तियाज अहमद

खेतासराय, जौनपुर (उत्तरशक्ति)। खेतासराय मनेछा स्थित मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल में उर्दू शिक्षिका रहीमा खातून का जन्मदिवस बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल देखने को मिला।

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के मैनेजर डॉ. आबिद खान ने रहीमा खातून को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज और

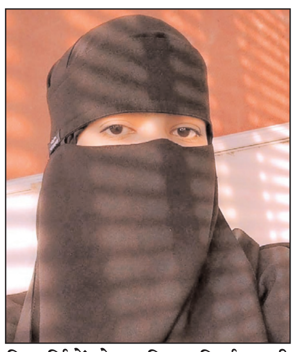

विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं।

इस अवसर पर प्रधानाचार्य इंतेखाब अहमद, सैय्यद तारिक, मो. राशिद, मेराज अहमद, रोहित यादव, राहुल गुप्ता, फैजान खान, सरफराज खान, शोएब, शबा परवीन, सोनम यादव, आयुषी यादव, अनीता गुप्ता, नजराना, अक्सा, खुशबू, खुशहाली सिद्दीकी, जोया जावेद, पूजा यादव, निधि कौशल और अचल पाण्डेय सहित विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके शैक्षणिक योगदान की सराहना की। जन्मदिवस समारोह के दौरान केक काटकर खुशियां साझा की गईं तथा सभी ने मिलकर इस खास अवसर को यादगार बनाया।

फाइलेरिया मरीजों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित, मरीजों को बांटी गई एमएमडीपी किट

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात कुमार के नेतृत्व में मुख्य

चिकित्सा अधिकारी सभागार में फाइलेरिया रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगता रोकथाम को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र सिंह ने की, जबकि जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार यादव की देखरेख में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

कार्यशाला में जिला मलेरिया अधिकारी सुनील कुमार यादव एवं डॉ. सिद्धार्थ दत्ता ने पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से फाइलेरिया के कारण, लक्षण, बचाव, जांच, उपचार और रुग्णता प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिभागियों को साफ-सफाई, धुलाई और नियमित एक्सरसाइज के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया। डॉ. मंजीत कुमार ने प्रश्नोत्तर सत्र के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया। विशेषज्ञों ने बताया कि फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके प्रमुख लक्षणों में हाथ-पैर, स्तन और अंडकोष में सूजन तथा पेशाब में सफेद पानी आना शामिल है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जनपद में फाइलेरिया के 5270 मरीज चिन्हित हैं, जिन्हें रुग्णता प्रबंधन एवं दिव्यांगता रोकथाम के तहत प्रशिक्षण और विशेष किट उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2025 में सभी मरीजों को किट वितरित की जा चुकी है, जबकि वर्ष 2026 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से किट वितरण का कार्य जारी है। कार्यशाला के दौरान पांच मरीजों को एमएमडीपी किट भी प्रदान की गई।

स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घरों के आसपास साफ-सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें और फाइलेरिया के लक्षण दिखने पर तत्काल नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच कराएं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना बनी सहारा, श्रमिक परिवारों के चेहरे पर आई मुस्कान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 'कन्या विवाह सहायता योजना' श्रमिक परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल मिल रहा है।

जनपद जौनपुर के विकासखंड जलालपुर के ग्राम सुल्तानपुर निवासी श्रमिक श्रीमती निर्मला देवी पत्नी दयाशंकर ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया था। योजना के तहत उन्हें 85,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई, जिससे विवाह का आयोजन सुगमता से संपन्न हो सका। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण विवाह की तैयारियों को लेकर चिंता थी, लेकिन शासन की इस योजना ने बड़ी मदद की। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार एवं श्रम विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

इसी क्रम में विकासखंड सिरकोनी के ग्राम शेखआलम निवासी श्रमिक संग्राम चौहान को भी योजना के अंतर्गत दो पुत्रियों के शादी के लिए 1,10,000 की सहायता राशि प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि इस सहायता से अपनी पुत्री का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न करने में काफी सहयोग मिला। उन्होंने कहा कि पहले आर्थिक तंगी के कारण विवाह की व्यवस्था करना कठिन लग रहा था, लेकिन शासन की इस योजना ने उन्हें नई उम्मीद दी।

सहायक श्रमायुक्त देवव्रत यादव ने बताया कि 'कन्या विवाह सहायता योजना' का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना के तहत पात्र श्रमिकों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

जनपद में श्रमिकों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र श्रमिक शासन की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। उन्होंने बताया है कि उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाभान्वित श्रमिकों की संख्या-210, कुल धनराशि रू0 1,16,20,000 से लाभान्वित किया जा चुका है।

राजकुमार सिंह को मुम्बई में मिला तरुण कला संगम पत्रकारिता पुरस्कार

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। मड़ियाहूं तहसील के मारिकपुर गाँव निवासी राजकुमार सिंह को भव्य कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने स्मृति चिन्ह के साथ दो लाख की नकद राशि मुंबई की प्रतिष्ठित सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था तरुण कला संगम द्वारा 9 मई की शाम को सम्राट होटल, चर्चगेट में आयोजित एक भव्य समारोह में नवभारत टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह को तरुण कला संगम पत्रकारिता पुरस्कार 2025 प्रदान किया

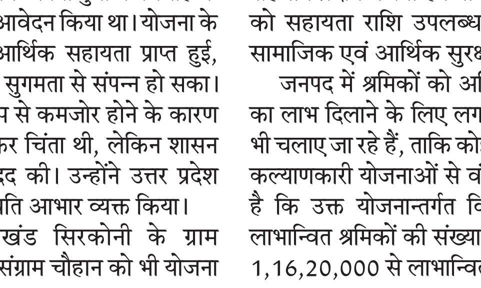

गया। समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारतीय ने की। समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, सम्मानित अतिथि के रूप में विधायक संजय उपाध्याय, आईएएस अधिकारी श्रीमती वी राधा, वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र द्विवेदी उपस्थित रहे। राजकुमार सिंह को पुरस्कार के रूप में स्मृति चिन्ह के साथ एक लाख रुए की नगद राशि प्रदान की गई। संस्था के अध्यक्ष चित्रसेन सिंह ने अपने स्वागत भाषण में संस्था द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। संस्था के संयोजक राधेश्याम मिश्रा, अभिषेक सिंह और वेदांत सिंह ने आए हुए अतिथियों का सम्मान किया। संस्था के महासचिव दीपक सिंह ने समस्त लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडे ने किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में भाजपा प्रवक्ता उदय प्रताप सिंह, पत्रकार आदित्य दुबे, पत्रकार विजय सिंह कौशिक, आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली, विनोद यादव, सुरेंद्र मिश्रा, ओम प्रकाश पांडे, नवीन पांडे, हरि मृदुल आदि का समावेश रहा। राजकुमार सिंह जौनपुर के मड़ियाहूं तहसील स्थित मारिकपुर गांव के रहने वाले हैं।

कर्तव्य निभाते-निभाते चली गई जान, सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद में सड़क हादसे में घायल होमगार्ड जवान अनिल कुमार दुबे की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, वहीं पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के बाद पुलिस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां बुलेट सवार दोनों युवकों का प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल अनिल कुमार दुबे को जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। होमगार्ड जवान की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि परिवार में पत्नी, दो बेटे और तीन बेटियां हैं। एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि दो बेटियों की शादी अभी बाकी है। डायल 112 प्रभारी मिथिलेश कुमार मिश्रा ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि अनिल कुमार दुबे बेहद जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ जवान थे, जिनकी कमी हमेशा महसूस की जाएगी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है।

गोमती नदी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत, प्रदूषण और सफाई परियोजना पर उठे सवाल

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिले में गोमती नदी का जलस्तर और पर्यावरणीय स्थिति लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है। बुधवार को नदी में बड़ी संख्या में मछलियां मृत अवस्था में पानी के ऊपर तैरती दिखाई दीं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मछलियों के मरने की खबर फैलते ही नदी किनारे लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग मृत मछलियों को पकड़ते भी नजर आए। इस घटना ने गोमती नदी के बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय संकट को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में लगातार गिर रहे गंदे नालों, बढ़ते प्रदूषण और भीषण गर्मी के कारण पानी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे मछलियां मर रही हैं। हालांकि मछलियों की मौत का वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। गौरतलब है कि गोमती नदी को स्वच्छ बनाने और नालों के पानी को शुद्ध कर नदी में प्रवाहित करने के लिए करीब 400 करोड़ रुपये की परियोजना चलाई गई थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लोग इस परियोजना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग से मामले की गंभीरता से जांच कर जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है, ताकि गोमती नदी के पर्यावरण और जलीय जीवन को बचाया जा सके।

मनरेगा कार्यों में गबन की शिकायत पर 23 मई को होगी पुन: जांच

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिला विकास अधिकारी मीनाक्षी देवी ने बताया कि ग्राम विशुनपुर (मझवारा), विकास खण्ड सिरकोनी निवासी रमेश कुमार चौबे द्वारा ग्राम पंचायत विशुनपुर मझवारा में मनरेगा योजनांतर्गत कराए गए कार्यों में कथित गबन की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मामले की जांच 07 अप्रैल 2026 को की गई थी। मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर अब मामले की दोबारा स्थलीय जांच कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए 23 मई 2026 को अपराह्न 2 बजे ग्राम पंचायत विशुनपुर मझवारा, विकास खण्ड सिरकोनी में जांच तिथि निर्धारित की गई है।

प्रशासन की ओर से संबंधित सचिव, ग्राम प्रधान, शिकायतकर्ता एवं अन्य संबंधित पक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे पंचायत भवन/ग्राम सचिवालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर आपत्तिकृत बिंदुओं से जुड़े अभिलेख, पत्रावली और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करें। जिला प्रशासन ने कहा है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी, ताकि शिकायत से जुड़े तथ्यों की सही स्थिति स्पष्ट हो सके।

टोटो रिक्शा से कार्यालय पहुंचीं पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद

सोनभद्र(उत्तरशक्ति)। प्रधानमंत्री के आह्वान पर ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुधवार को रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने अनूठी पहल की। उन्होंने अपने आवास उरमौरा से नगर पालिका परिषद कार्यालय तक बैटरी चालित टोटो रिक्शा से यात्रा कर आमजन को पेट्रोल और डीजल की बचत का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की अपील करते हुए कहा कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव संभव हैं। यदि लोग दैनिक जीवन में ईंधन की खपत कम करने का संकल्प लें तो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक बचत भी की जा सकती है। उनकी इस पहल की स्थानीय लोगों ने सराहना की और इसे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कदम बताया।

फर्जी डॉक्टर की शिकायत को लेकर भिड़े व्यापारी और डॉक्टर, जौनपुर में मारपीट से मचा हड़कंप

डॉ.इम्तियाज अहमद

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शहर कोतवाली क्षेत्र के मंडी नसीब खां मोहल्ले में मंगलवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब नगर उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष और डॉक्टर पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए।

जानकारी के अनुसार, नगर उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष राधे रमण जायसवाल अपनी दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले डॉ. अनुराग साहू अपने पिता धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ वहां पहुंचे। आरोप है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी से फर्जी डॉक्टर होने की शिकायत को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।

घटना में राधे रमण जायसवाल और उनके पुत्र निश्चल जायसवाल घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से धर्मेंद्र कुमार साहू और डॉ. अनुराग साहू को भी चोटें आई हैं।

सूचना मिलते ही भंडारी चौकी प्रभारी जयदीप कुमार कोल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर उपचार एवं मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया।

फिलहाल दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिशें जारी हैं। समाचार लिखे जाने तक किसी भी पक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

जौनपुर में गन्ने की जूस मशीन बनी हादसे की वजह, महिला का हाथ काटकर बचानी पड़ी जान

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। शहर में सड़क किनारे लगाई जा रही गन्ने की जूस मशीनें अब लोगों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। बुधवार दोपहर लाइन बाजार थाना क्षेत्र के जेसीज चौराहे पर एक दर्दनाक हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उसका हाथ काटना पड़ा।

जानकारी के अनुसार सुरियावां थाना क्षेत्र के महजूदा गांव निवासी अजय कुमार चौहान की पत्नी रिंकी चौहान (28) अपने बच्चों के साथ मायके सरायख्वाजा जा रही थीं। रास्ते में वह जेसीज चौराहे पर रुकीं और सड़क किनारे लगे ठेले पर गन्ने का जूस पीने लगीं। इसी दौरान लापरवाही से संचालित मशीन की चपेट में आने से उनका बायां हाथ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। महिला के साथ

मौजूद बच्चे मां की हालत देखकर रोने-बिलखने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए हाथ अलग कर उनकी जान बचाई।

इस घटना के बाद शहर में सड़क किनारे संचालित हो रही गन्ने के जूस मशीनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जेसीज चौराहा, चहारसू चौराहा, कोतवाली चौराहा, अंबेडकर तिराहा, सब्जी मंडी और रेलवे स्टेशन समेत कई स्थानों पर अव्यवस्थित तरीके से लगाई गई मशीनें आम लोगों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए खतरा बन चुकी हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि इन मशीनों से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है और सड़क किनारे अतिक्रमण होने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे मशीन संचालकों के खिलाफ अभियान चलाकर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है।

किसान दिवस में जल संरक्षण, फसल बीमा एवं आधुनिक खेती पर जोर

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। किसान दिवस के अवसर पर जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों से संबंधित जानकारी किसानों को प्रदान की गई।

जिलाधिकारी ने जनपद के किसानों को परंपरागत खेती के साथ-साथ केला, मशरूम एवं ड्रैगन फ्रूट, खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को नैपियर घास की खेती करने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने सभी किसानों से अपनी फसलों का बीमा कराना सुनिश्चित करने को कहा, ताकि प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य परिस्थितियों में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि कार्ययोजना बनाकर टेल

तक पानी पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनपद में भू-जल स्तर लगातार कम होने पर चिंता व्यक्त करते हुए गांवों के पुराने कुओं को पुनर्जीवित करने की पहल शुरू करने की अपील की।

बैठक में जल संरक्षण एवं पौधरोपण को बढ़ावा देने पर विशेष चर्चा की गई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान दिवस में किसानों द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करते हुए किसानों को अवगत कराया जाए। संचालन उप परियोजना निदेशक आत्मा डा.रमेश चंद्र यादव ने किया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, उप निदेशक कृषि बी0बी0 द्विवेदी सहित जिला कृषि अधिकारी विनय सिंह, जिला उद्यान अधिकारी डा. सीमा सिंह राणा, किसान यूनियन के पदाधिकारी सहित किसानगण अन्य उपस्थित रहे।

जौनपुर में स्कूली वाहनों को लेकर प्रशासन सख्त, डीएम ने दिए कड़े निर्देश

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। जनपद में स्कूली वाहनों की सुरक्षा और मानकों के पालन को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी मान्यता प्राप्त सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के स्कूलों एवं कॉलेजों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। साथ ही एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एआरटीओ, एबीएसए, एएसपी, फायर विभाग तथा परिवहन, शिक्षा और ट्रैफिक विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

बैठक में बताया गया कि वढकरस्टढ पोर्टल पर जिले के 1499 स्कूली वाहनों को ऑनबोर्ड किया गया है। जांच के दौरान 603 वाहनों के परमिट, बीमा और फिटनेस संबंधी दस्तावेज अपूर्ण पाए गए हैं।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन वाहनों के दस्तावेज अधूरे हैं, उनका संचालन तत्काल प्रभाव से रोका जाए। उन्होंने कहा कि

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी स्कूल प्रबंधन अपने वाहनों के परमिट, बीमा, फिटनेस एवं अन्य आवश्यक प्रपत्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

डीएम ने चेतावनी दी कि बिना मानक पूरे किए किसी भी स्कूली वाहन का संचालन पाए जाने पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्कूली वाहनों की निर्धारित गति सीमा का पालन कराने, वाहनों को पीले रंग के मानकों के अनुरूप रखने तथा प्रशिक्षित चालकों से ही वाहन संचालन कराने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही सभी स्कूली वाहनों पर आपातकालीन मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संपर्क किया जा सके।

बैठक में अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड ने अपने 10वें संस्करण के लिए आवेदन आमंत्रित किए

मुंबई। दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग संस्थाओं में से एक, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड के 10वें एडिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह भारत में अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग छात्रों के लिए सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में से एक है। इस खास मौके पर, स्कॉलरशिप ने अपनी कुल इनामी राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। आवेदन अब शुरू हो गए हैं और 15 जून 2026 को बंद हो जाएंगे। पिछले एक दशक में, आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड ने उन छात्रों को पहचान दी है जो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके असल दुनिया की समस्याओं को हल करने में भी आगे रहते हैं। हेल्थकेयर तक पहुंच और टिकाऊ खेती से लेकर कचरा प्रबंधन और सहायक टेक्नोलॉजी तक, प्रतिभागियों ने ऐसे इनोवेशन दिखाए हैं जिनका समाज पर गहरा असर पड़ता है। पिछले विजेता और फाइनलिस्ट दुनिया भर में मशहूर संस्थाओं और संगठनों, जैसे Apple, Google, NASA, MIT और कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में काम करने के मौके पा चुके हैं। इससे पता चलता है कि यह प्रोग्राम किस तरह के बेहतरीन टैलेंट को बढ़ावा दे रहा है।

10वें एडिशन के बारे में बात करते हुए, आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड की सलाहकार समिति के चेयरमैन, प्रो. अभिजीत चक्रवर्ती ने कहा: IET इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड के जरिए, हमारा मकसद छात्रों को असल दुनिया की चुनौतियों के बारे में गहराई से सोचने और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों को नए और प्रैक्टिकल तरीकों से इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। पिछले कुछ सालों में, हमने पूरे देश से बेहतरीन टैलेंट को उभरते हुए देखा है, और 10वां एडिशन इस सफर को आगे बढ़ाने में एक अहम पड़ाव है।

महाराणा प्रताप जयंती, बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव एवं परिवार मिलन समारोह संपन्न

-प्रेम चंद मिश्रा

नालासोपारा (उत्तर शक्ति) राजपूताना परिवार फाउंडेशन के तत्वावधान में चैत्र महोत्सव, संवत 2083 का भव्य स्वागत श्रद्धा, शौर्य एवं संस्कार के साथ संपन्न हुआ। यह आयोजन श्री बालाजी हॉल वसंत नगरी नालासोपारा पूर्व में रखा गया था। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति एवं क्षत्रिय धर्म का जीवंत उत्सव था। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा महापुरुषों को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप की लौ ने जैसे ही सभा को आलोकित किया, पूरा प्रांगण जय भवानी के उद्घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण कारगिल के वीर योद्धा नायक दीपचंद पंचग्रामी रहे, जिनका वीरता के लिए भव्य सम्मान किया गया। जनता ने खड़े होकर अपने नायक का अभिनंदन किया। विश्वामित्र की भूमिका में ?महर्षि? टाइटल से अलंकृत नालासोपारा के अघोर पीठाधीश्वर महंत बाबा अलख राम ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में सनातन का आध्यात्मिक

महत्व बताया एवं क्षत्रिय धर्म पर जोर देते हुए कहा कि धर्म की रक्षा ही क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य है।

मुख्य वक्ता डॉ. ओमप्रकाश दुबे ने मार्गदर्शन देते हुए कहा,_आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे तब एक जनवरी को नववर्ष नही मनाया जाता था, तब हमारे यहां केवल विक्रम संवत ही चलता था तथा वसंत पंचमी से होली तक पिछले वर्ष की विदाई की जाती थी एवं संपूर्ण चैत्र माह में चैत्र महोत्सव मनाकर नववर्ष का स्वागत किया जाता था । हमारे देश का हर वर्ग पूरे उत्साह से चैत्र महोत्सव मनाता था. मंच संचालन की बागडोर श्रीप्रकाश सिंह ने कुशलता से संभाली। पधारे हुए सभी अतिथियों का सत्कार राजपूताना परिवार फाउंडेशन के अध्यक्ष दद्दन सिंह चौहान ने शॉल एवं श्रीफल भेंट कर किया।

कार्यक्रम में सम्मानमूर्ति के रूप में पधारीं क्षत्राणी नगर सेवीका समाजसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु श्रीमती बबीता देवराज सिंह, एकता सिंह, पिंकी राठौर, प्रदीपिका सिंह, जेपी सिंह, अभय कक्कड़, अशोक शेलके आदि को सम्मानित किया गया। नासिक से पधारे राजेंद्र सिंह चौहान, रामदुलार सिंह, लाल साहब सिंह, वीरेंद्र सिंह तोमर, कुमार शैलेंद्र सिंह, जय प्रकाश सिंह एवं श्रीमती रीता सिंह सहित अनेक आर्मी एवं नेवी के जवानों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गौरवान्वित किया। सभी वीरों ने महाराणा प्रताप जयंती एवं बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

गायक दामोदर राव, नंदिनी तिवारी, पूनम सिंह एवं सूरज सिंह 'तूफानी' ने अपनी सुमधुर गायकी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भक्ति और वीर रस के गीतों पर पूरा पंडाल झूम उठा। राजपूताना परिवार के सदस्य - सर्वश्री वीरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, राजेश सिंह सूर्यवंशी, बबन सिंह, ललन सिंह, अरबिंद सिंह मनोज सिंह राकेश सिंह नाहर सिंह केदार सिंह रूपेश सिंह अजय सिंह सरवन सिंह सिसोदिया नरेंद्र सिंह राणावत वीरभद्र सिंह जडेजा अश्विन सिंह जाडेजा स्वरूप सिंह जडेजा जयेंद्र सिंह जडेजा जगदीश सिंह जडेजा सत्येंद्र रावत सुनील सिंह, मोहित सिंह, विजय सिंह, विनोद सिंह, राधा रमन सिंह, अमित सिंह, नाहर सिंह, भावेश सिंह, रोहित सिंह, राम सिंह, केदारनाथ सिंह, राज चौरसिया, जयकुमार यादव एवं संस्था के सभी सदस्यो पूरे जोश-ओ-खरोश के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। श्रीमती अंजू सिंह, खुशबू सिंह, आशा सिंह, गरिमा सिंह, सुषमा सिंह, संध्या सिंह, किरण सिंह, बबीता सिंह सहित तमाम बहनों एवं माताओं ने भाग लिया। सुरुचिपूर्ण भोज का आनंद लिया एवं प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

रैपिडो और महाआईटी के बीच समझौता, महाराष्ट्र में कैप्टन सत्यापन और डिजिटल नागरिक पहुंच होगी मजबूत

मुंबई। रैपिडो की मूल कंपनी रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे किफायती वन-स्टॉप मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है, ने महाराष्ट्र सरकार की डिजिटल गवर्नेंस और आईसीटी पहलों की नोडल एजेंसी महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महाआईटी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य महाराष्ट्र में नागरिक जागरूकता, डिजिटल समावेशन और भरोसेमंद डिजिटल मोबिलिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सहयोग के अवसर तलाशना है। इस सहयोग के तहत रैपिडो अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और बड़े कैप्टन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए आपले सरकार, महाआईडी, महासारथी और महाआईटी की ओर से चलाई जा रही अन्य नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक सेवा प्लेटफॉर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।

महाआईटी के प्रवक्ता सुभाष शेलके ने कहा, हमें खुशी है कि हम रैपिडो के साथ मिलकर यह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और बड़े जमीनी मोबिलिटी नेटवर्क महाराष्ट्र की व्यापक डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक जागरूकता के लक्ष्यों को सहयोग दे सकते हैं। इस समझौते का एक अहम हिस्सा है रैपिडो कैप्टन्स के लिए डिजिटल रूप से सत्यापित ऑनबोर्डिंग और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया, जिसमें महाआईडी के साथ एकीकरण भी शामिल है, ताकि राज्य में भरोसा, पारदर्शिता और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ऐसे रैपिडो कैप्टन्स को जमीनी स्तर पर डिजिटल जानकारी पहुंचाने वाले राजदूत के रूप में तैयार करने में भी बड़ी संभावना नजर आती है, जो महाराष्ट्र भर के नागरिकों के बीच सार्वजनिक डिजिटल सेवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनका इस्तेमाल बढ़ाने में मदद करेंगे। इस साझेदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए रैपिडो के को-फाउंडर पवन गुंटुपल्ली ने कहा, रैपिडो में हमारा हमेशा से मानना रहा है कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर भरोसा, सुरक्षा और नागरिक जागरूकता बढ़ाने में और बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। महाआईटी के साथ इस सहयोग के जरिए हम अपने डिजिटल इकोसिस्टम और बड़े कैप्टन नेटवर्क का इस्तेमाल सार्वजनिक डिजिटल पहलों को सहयोग देने के लिए करना चाहते हैं, साथ ही महाराष्ट्र में नागरिकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद मोबिलिटी अनुभव को और बेहतर बनाते रहेंगे।

इंदौर में पानी की राजनीति पर गरमाई सियासत, महापौर के घर पहुंचे विधायक खुलकर की तारीफ

-प्रणित नरेंद्र तिवारी

इंदौर (उत्तर शक्ति)। इंदौर में जल संकट और पानी की टंकी बनाने को लेकर मंगलवार को भाजपा के दो बड़े चेहरे आमने-सामने नजर आए, लेकिन महज 24 घंटे बाद बुधवार को तस्वीर पूरी तरह बदल गई। विधायक महेंद्र हार्डिया ने विधानसभा क्रमांक-5 के साथ भेदभाव और पानी की टंकियों को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। बुधवार को वे भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के साथ महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निवास पहुंचे और जल वितरण व्यवस्था की खुलकर सराहना की। मंगलवार को सामने आई राजनीतिक तनातनी ने शहर की राजनीति में हलचल मचा दी थी। जानकारी सामने आई थी कि अमृत-2 योजना के तहत बनने वाली पानी की टंकियों को लेकर विधायक हार्डिया खासे नाराज हैं। उनका

आरोप था कि शहर में 40 टंकियां बनाई जा रही हैं, लेकिन विधानसभा-5 को सिर्फ एक टंकी दी गई। बताया गया कि जल संकट और आधी भर रही टंकियों को लेकर हार्डिया के समर्थक पार्षद प्रदर्शन की तैयारी में थे। मामला इतना बढ़ा कि भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान भी तनाव की स्थिति बन गई और विधायक नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर चले गए। सूत्रों के मुताबिक हार्डिया ने भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था। वहीं महापौर पक्ष का कहना था कि विधानसभा-5 में पहले से सबसे ज्यादा टंकियां बनाई गई हैं और नई टंकियों को लेकर विधायक से लोकेशन भी मांगी गई थी।

बुधवार को माहौल पूरी तरह बदला नजर आया। विधायक महेंद्र हार्डिया और नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा महापौर निवास पहुंचे, जहां जल संकट और वितरण व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान विधायक हार्डिया ने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम की टीम लगातार दिन-रात मेहनत कर रही है, जिसके कारण शहर में पानी का वितरण सुचारु रूप से हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को भाजपा के भीतर बढ़ती नाराजगी को शांत करने और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।

ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पीएसी तिराहे पर सघन चेकिंग अभियान!

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत मंगलवार को पीएसी तिराहे पर सघन वाहन चेकिंग की गई। अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी संजय मिश्रा, कस्बा प्रभारी शिवम सोनी ने पुलिस बल के साथ स्वयं सड़क पर उतरकर किया।

चेकिंग के दौरान दोपहिया व चारपहिया वाहनों को रोककर उनकी गहन तलाशी ली गई। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट,नंबर प्लेट की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की गई। कस्बा प्रभारी शिवम सोनी ने बताया कि ऑपरेशन चक्रव्यूह का उद्देश्य अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना है, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। उन्होंने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की। अभियान के दौरान पीएसी तिराहे पर कुछ देर के लिए वाहनों की लंबी कतार भी देखी गई, लेकिन पुलिस की सक्रियता से व्यवस्था सामान्य बनी रही।

हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

वाराणसी (उत्तरशक्ति)। जनपद में दुकान कब्जा करने का विरोध करने पर व्यवसायी पर हमला कर लूटपाट करने और दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त करने के मामले में अदालत ने हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोतवाली थाना प्रभारी को दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) अमित कुमार यादव की अदालत ने यह आदेश हरतीरथ निवासी वादी मुकदमा मुकुंद यादव की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया। प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा मुकुंद यादव ने अपने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव व धनंजय कुमार के जरिए अदालत में बीएनएनएस की धारा 173(4) के जरिए प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप था कि हरतीरथ चौराहे पर उसकी तीन दुकाने है, जो व्यापारिक दृष्टि से काफी कीमती है। जिसमें एक दुकान में जनरल स्टोर, दूसरी दुकान में चाय व दही-मलाई की तथा तीसरी दुकान में बिल्डिंग मैटेरियल, सीमेंट आदि की दुकाने है। जिससे वह और उसके पुत्रगण व्यापार कर अपना व अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते हैं। इसमें से एक दुकान पर विपक्षीगण जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। विपक्षीगण उमेश सिंह व मुकेश सिंह द्वारा कुछ दिनों पूर्व पार्थी के हरतीरथ स्थित दुकान की माँग की गयी थी। जब उसने इंकार कर दिया तो विपक्षीगण काफी आग बबूला हो गये और बोले कि दुकान तो हम किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। अपनी इसी मंशा की पूर्ति करने के लिए 18 मार्च 2026 को शाम 4 बजे उमेश सिंह, मुकेश सिंह व कुणाल सिंह उर्फ गोलू अपने हिन्दू युवा वाहिनी के 12 से 15 अज्ञात साथियों के साथ उसके हरतीरथ स्थित मकान में जबरदस्ती घुस आये और घर में अन्दर रखे बिल्डिंग मैटेरियल के सामान को तोड़-फोड़ कर गिराने लगे। जब उसने विरोध किया तो वे लोग उस पर हमला कर दिए। जिससे उसे गंभीर चोटें आई। साथ ही उसका लगभग 1.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ और वे लोग दुकान में रखा कीमती सामान उठा ले गए। वादी ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं। साथ ही हिन्दू युवा वाहिनी के दबाव में उनके सदस्य उमेश सिंह ने 25 मार्च 2026 को विलम्ब से प्रस्तुत की गयी प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ ही विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।

बारातियों पर बदमाशों का हमला, छिनैती का प्रयास

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के बेलाव घाट पूल के पास मंगलवार की रात को वापस लौट रहे बारातियों पर बदमाशों ने हमला करके घायल कर दिया। घटना में दूल्हे के भाई का हाथ फैक्चर हो गया। घटना की सूचना पर जफराबाद, जलालपुर तथा केराकत पुलिस मौके पर पहुंच गई। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर दबिश दी गयी। बदमाशों पर पहले कई संगीन धारा के मुकदमे में जेल जा चुके है।

जफराबाद क्षेत्र के सखोई गांव निवासी रुस्तम अली की पुत्री की शादी थी। बारात मुफ्तीगंज के पास नयेपुरा गांव से आई थी। बारात रात को आठ बजे आयी।उसके बाद खाना के बाद बारात के लोग एक चार पहिया वाहन से वापस घर लौटने रहे थे। सखोई गांव से मात्र एक किमी ही दूर बाराती बेलाव घाट पूल के पास पहुंचे थे कि बदमाशों ने चार पहिया वाहन को रुकवा लिया। उसके बाद उन लोगों ने गाली गलौज किया।

आरोप है उन लोगो ने छिनैती का भी प्रयास किया। उसका विरोध करने पर बारातियों को मारने पीटने लगें। बारातियों ने सखोई गांव में दूल्हे के भाई को सूचना दिया। सूचना मिलते ही दूल्हे के भाई अखलाख पुत्र सज्जाद अपने एक मित्र के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए।बारात की वाहन चली गयी। उसके बाद उक्त बदमाशों ने मारपीट करने लगे।जिसमे अखलाख का हाथ फैक्चर हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गयी। सूचना के बाद बार्डर का मामला होने के चलते जहां जलालपुर तथा जफराबाद के थानाप्रभारी मय फोर्स मौके पर पहुंच गए।वही एक बदमाश जलालपुर का होने की सूचना पर जलालपुर के थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। पुलिस की टीमो ने रात को कई स्थानों पर दबिश दिया।

दुकान की छत से सेंध लगाकर किराना स्टोर से दो लाख नगदी चोरी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। नगर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र के शीतला चौकियां के रामदासपुर नेवादा क्षेत्र में किराना स्टोर की छत से सेंध लगाकर चोरों ने दो लाख नगदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह 8 बजे दुकानदार ने दुकान खोला तो सामान बिखरा पड़ा देखा गल्ला चेक किया तो 2 लाख नगदी गायब थे। घटना से दुकानदार के होश उड़ गये। सूचना पर शीतला चौकिया चौकी पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गयी। दुकानदार ने लिखित तहरीर पुलिस को दिया है। जानकारी के अनुसार शीतला चौकियां चौराहा के समीप रामदासपुर नेवादा क्षेत्र निवासी कुंदन जायसवाल पुत्र सुरेंद्र जायसवाल की क्षेत्र में ही किराने की दुकान है। बीते बुधवार रात्रि कुंदन दुकान बंद कर-के घर चला गया। सुबह जाकर दुकान खोला तो सारा सामान दुकान का बिखरा पड़ा देखा। गल्ले से 2 लाख नगदी गायब था। छत पर जाकर देखा तो पता चला की सिढी के बगल से चोरों ने सेंध लगाकर घटना को अंजाम दिया है। कुंदन ने बताया कि चोरी हुए 2 लाख में से 20.000 के सिक्के थे, बाकी 1 लाख 80000 रुपए के नोट थे पुलिस मामले जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।

इसुजु मोटर्स इंडिया ने अपने इसुजु डी-मैक्स एस-कैब के लिए बेहद शानदार लीजिंग सॉल्यूशन पेश किया

मुंबई। इसुजु मोटर्स लिमिटेड की सहायक कंपनी तथा भारत में कामर्शियल वाहनों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक, इसुजु मोटर्स इंडिया ने आज इसुजु डी-मैक्स एस-कैब को लीज पर देने के एक नए मॉडल को पेश करने की घोषणा की। चूँकि भारत में अब अलग-अलग तरह के बिजनेस के लिए वाहनों को लीज पर लेना एक पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है, जिसे देखते हुए इस नए मॉडल को पेश किया गया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को कमर्शियल वाहन खरीदने के बोझ के बिना, उनके इस्तेमाल का एक अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक तरीका प्रदान करना है। इस पहल में मुख्य रूप से इसुजु डी-मैक्स एस-कैब को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि यह वाहन बेहद मजबूत और भरोसेमंद होने के साथ-साथ अलग-अलग तरह के व्यावसायिक कामों में इस्तेमाल किए जाने के लिए जाना जाता है। वाहनों को लीज पर उपलब्ध कराने के इस मॉडल को बिजनेस के कामकाज में सहूलियत और पैसों की बचत के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए अलग-अलग तरह के बिजनेस और फ्लीट ऑपरेटर एक निश्चित समय के लिए वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे शुरूआत में बड़ा पैसा लगाने, वाहन की कीमत घटने या उसे बाद में कभी बेचने जैसी बातों से जुड़ी चिंताएँ खत्म हो जाती हैं।

इस घोषणा के बारे में बात करते हुए, इसुजु मोटर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, राजेश मित्तल ने कहा, इसुजु पूरी दुनिया के अलग-अलग बाजारों में भरोसेमंद, टिकाऊ, व्यवसायों को आगे बढ़ाने में मददगार और बेहद कुशल कमर्शियल वाहन उपलब्ध कराने के लिए मशहूर है। इसुजु मोटर्स इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ताकेशी हिरानो ने कहा, हमें इसुजु डी-मैक्स एस-कैब के लिए लीज़िंग मॉडल पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि इसे ग्राहकों के लिए कमर्शियल वाहन का मालिक बनना ज्यादा आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसुजु डी-मैक्स एस-कैब ने अपनी दमदार बनावट और बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर कमर्शियल वाहनों की दुनिया में एक बेहद भरोसेमंद वाहन के रूप में अपनी खास पहचान बनाई है।

इंतजार आखिरकार खत्म हुआ — सैराब 2 जून से शाम 7:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर!

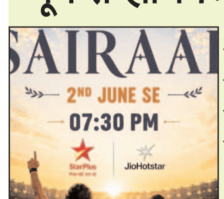

मुंबई। अपने दिलचस्प टाइटल अनाउंसमेंट के साथ दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाने के बाद, स्टार प्लस ने आखिरकार अपने बहुप्रतीक्षित नए शो सैराब की लॉन्च डेट का ऐलान कर दिया है। यह शो 2 जून 2026 से हर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे प्रसारित होगा। सैराब दर्शकों को भावनाओं से भरी एक नई कहानी से रूबरू कराएगा, जिसमें रिश्तों की उलझनें, दिल को छू लेने वाले एहसास और दिलचस्प कहानी देखने को मिलेगी। सैराब के पहले ऐलान के बाद से ही दर्शक बेसब्री से जानना चाहते थे कि स्टार प्लस इस बार उनके लिए क्या नया लेकर आ रहा है। हालांकि शो की कहानी और किरदारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां अभी भी राज रखी गई हैं, लेकिन केवल इसकी लॉन्च डेट के खुलासे ने ही दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह पैदा कर दिया है। हर पीढ़ी के दर्शकों के दिलों को छू लेने वाली कहानियां प्रस्तुत करने के लिए पहचाना जाने वाला स्टार प्लस अब सैराब के जरिए दर्शकों को एक नई और भावनात्मक दुनिया से रूबरू कराने जा रहा है। अब जब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो दर्शक 2 जून से सैराब की इस खास दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाएं। देखना न भूलें सैराब, 2 जून 2026 से हर सोमवार से रविवार शाम 7:30 बजे, सिर्फ स्टार प्लस पर देखे।

46 विभिन्न परियोजनाओं का किया भूमि पूजन व लोकार्पण

वाराणसी (उत्तरशक्ति) । जनपद के रोहनिया विधानसभा रोहनिया क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति प्रदान करते हुए रोहनिया विधायक डॉ. सुनील पटेल ने मिसिरपुर में बुधवार को 22.40 करोड़ रुपये लागत की 46 विकास परियोजनाओं का विधिवत हवन पूजन के साथ शिलापट्ट का अनावरण कर भूमि पूजन, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।मुख्य अतिथि विधायक डॉ. सुनील पटेल ने कहा कि रोहनिया विधानसभा क्षेत्र को आधुनिक और बेहतर सुविधाओं से जोड़ना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में सड़क, संपर्क मार्ग और आधारभूत सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए तेजी से कार्य कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।विधायक द्वारा सभी उपस्थित जनता जनार्दन को अंगवस्त्र भेंट किये। कार्यक्रम के अध्यक्षता बसंत लाल पटेल तथा संचालन दिनेश पटेल धन्यवाद ज्ञापन अजीत पटेल ने की। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद पटेल क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ नरेंद्र पटेल, राष्ट्रीय सचिव मनीष सिंह, अजीत पटेल, उदय प्रधान, राकेश यादव, महेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव उमेश पटेल, डॉक्टर महेंद्र सिंह पटेल, अनीता पटेल, जेई महेंद्र सिंह यादव, हरीश विद्यार्थी,उमेश सिंह, आदर्श पटेल, चंद्रशेखर पटेल, दिनेश पटेल, प्रेम पटेल,राम सिंह वर्मा, राजकुमार वर्मा,जे पी पटेल ,राम सकल मास्टर, ओम प्रकाश सिंह, रामधन मास्टर,भरत पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे।

आदेश की धज्जियां उड़ाने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 13 लाख रुपए की RC जारी

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। अदालत के आदेश को हल्के में लेना एक जानी-मानी बीमा कंपनी को भारी पड़ गया है। सड़क हादसे के शिकार एक होनहार छात्र को मुआवजा न देकर मनमानी करने वाली नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के खिलाफ कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के जज मनोज कुमार अग्रवाल ने कड़ा फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी के खिलाफ कलेक्टर के माध्यम से 13 लाख रुपये की रिकवरी सार्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दी है। कोर्ट के इस कड़े तेवर से बीमा महकमे में हड़कंप मच गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारीख तय की गई है। मामला बक्सा थाना क्षेत्र के शंभूगंज बाजार का है। दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष उपाध्याय (निवासी सवंसा, बक्सा) का बेटा चक्रवर्ती प्रभाकर उपाध्याय चार साल पहले कक्षा 11वीं का छात्र था। वह साइकिल से बाजार जा रहा था, तभी एक बेकाबू ऑटो रिक्शा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस भयानक हादसे में चक्रवर्ती गंभीर रूप सघायल हो गया, जिसके बाद वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उसका लंबा इलाज चला।

न्याय की आस में पीड़ित परिवार ने ऑटो मालिक संतोष उपाध्याय, चालक प्रेम शंकर उपाध्याय और बीमा कंपनी (नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के माध्यम से क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माना कि हादसा ऑटो चालक की घोर लापरवाही और उपेक्षा के कारण हुआ था। चूंकि ऑटो का बीमा था, इसलिए कोर्ट ने 24 दिसंबर 2025 को बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि वह पीड़ित को ब्याज सहित 13 लाख की क्षतिपूर्ति राशि 2 महीने के भीतर अदा करे।

बीमा कंपनी ने कोर्ट की समय सीमा (2 महीने) बीत जाने के बाद भी फूटी कौड़ी नहीं चुकाई। कंपनी के इस अड़ियल और संवेदनहीन रवैए के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने कोर्ट में रिकवरी (वसूली) के लिए प्रार्थना पत्र दिया।अदालत ने कंपनी को बकाए की नोटिस भी जारी की, लेकिन जब रसूखदार कंपनी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, तो ट्रिब्यूनल जज ने कानूनी चाबुक चलाते हुए सीधे कलेक्टर के जरिए आरसी जारी कर दी। अब प्रशासन इस रकम की वसूली कंपनी से कड़ाई से करेगा। यह फैसला उन कंपनियों के मुंह पर तमाचा है जो प्रीमियम तो समय पर वसूलती हैं, लेकिन क्लेम देने के वक्त पीड़ितों को अदालतों के चक्कर कटवाती हैं। अधिवक्ता पुत्र को न्यायःचार साल के लंबे इंतजार और दर्द के बाद आखिरकार कानून ने पीड़ित छात्र और उसके अधिवक्ता पिता के हक में बड़ा फैसला सुनाया।

कस्टमाइज्ड स्पेशल सर्विस वैल्यू पैकेज कार को ठंडा और सड़क पर तैयार रखेंगे : मुथन्ना

मुजफ्फरपुर। कस्टमर-फर्स्ट दर्शन के साथ अपने ग्राहकों को बेहतरीन सर्विस अनुभव देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ग्राहक इनसाइट्स के आधार पर हमने नई कारों, यूज्ड कारों और आफ्टर-सेल्स सर्विस पर शानदार समर स्कीम्स तैयार की हैं। हमारे कस्टमाइज्ड स्पेशल सर्विस वैल्यू पैकेज आपकी कार को ठंडा और सड़क पर तैयार रखेंगे। ये बातें टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के मेगा समर सेलिब्रेशन 2026 की शुरूआत की घोषणा पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, नॉर्थ रीजन के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ रिप्रेजेंटेटिव मुथन्ना ने कहीं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि यह कैंपेन ओनरशिप संतुष्टि को बढ़ाएगा और टोयोटा वाहन चलाने का आनंद और मजबूत करेगा।

बारातियों पर बदमाशों का हमला, छिनैती का प्रयास

जौनपुर (उत्तरशक्ति)। केराकत कोतवाली क्षेत्र के बेलाव घाट पूल के पास मंगलवार की रात को वापस लौट रहे बारातियों पर बदमाशों ने हमला करके घायल कर दिया। घटना में दूल्हे के भाई का हाथ फैक्चर हो गया। घटना की सूचना पर जफराबाद, जलालपुर तथा केराकत पुलिस मौके पर पहुंच गई। बदमाशों को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर दबिश दी गयी। बदमाशों पर पहले कई संगीन धारा के मुकदमे में जेल जा चुके है। जफराबाद क्षेत्र के सखोई गांव निवासी रुस्तम अली की पुत्री की शादी थी। बारात मुफ्तीगंज के पास नयेपुरा गांव से आई थी। बारात रात को आठ बजे आयी।उसके बाद खाना के बाद बारात के लोग एक चार पहिया वाहन से वापस घर लौटने रहे थे। सखोई गांव से मात्र एक किमी ही दूर बाराती बेलाव घाट पूल के पास पहुंचे थे कि बदमाशों ने चार पहिया वाहन को रुकवा लिया। उसके बाद उन लोगों ने गाली गलौज किया। आरोप है उन लोगो ने छिनैती का भी प्रयास किया। उसका विरोध करने पर बारातियों को मारने पीटने लगें।बारातियों ने सखोई गांव में दूल्हे के भाई को सूचना दिया। सूचना मिलते ही दूल्हे के भाई अखलाख पुत्र सज्जाद अपने एक मित्र के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए।बारात की वाहन चली गयी। उसके बाद उक्त बदमाशों ने मारपीट करने लगे।जिसमे अखलाख का हाथ फैक्चर हो गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गयी। सूचना के बाद बार्डर का मामला होने के चलते जहां जलालपुर तथा जफराबाद के थानाप्रभारी मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। वही एक बदमाश जलालपुर का होने की सूचना पर जलालपुर के थानाध्यक्ष प्रशांत सिंह मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। पुलिस की टीमो ने रात को कई स्थानों पर दबिश दिया।

नगरसेविका अपर्णा पाटील के जनसंपर्क कार्यालय में डॉक्यूमेंट कैंप आयोजित

वसईरोड। वॉर्ड क्रमांक 23 स्थित जनसंपर्क कार्यालय, ओम नगर, वसई रोड (पश्चिम) में आज नगरसेविका अपर्णा पाटील के नेतृत्व में आयोजित डॉक्यूमेंट कैंप को नागरिकों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला। कैंप में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर विभिन्न सरकारी दस्तावेजों से जुड़ी प्रक्रियाएँ पूरी कीं। इस विशेष कैंप में आयुष्मान कार्ड, सीनियर सिटीजन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट तथा वोटर आइडेंटिटी कार्ड (नया एवं सुधार) जैसी आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराई गईं। सुबह से ही नागरिकों की भारी भीड़ देखने को मिली और लोगों ने उत्साहपूर्वक सरकारी दस्तावेज बनवाने के लिए आवेदन किए। कैंप का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सुविधाएँ सरल, सुविधाजनक और सही मार्गदर्शन के साथ उपलब्ध कराना था। आयोजन को मिले सकारात्मक प्रतिसाद से आयोजक मंडल ने संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें सुश्री निम्मी दोशी (नगरसेविका), मैथ्यू कोलासो (डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी फ्रंट), मिस्टर छोटू आनंद (पूर्व कॉपोरेटर), मिस्टर हरीश बेदी (कन्वीनर, वर्कर्स फ्रंट), मिस्टर मनोज चौटालिया (बोर्ड सेक्रेटरी), मिस्टर लालजी कनौजिया (वसई रोड बोर्ड), मिस्टर नंदकिशोर पवार, मिस पूर्णिमा प्रमाणिक, मिस्टर राजू प्रजापति, मिस्टर निपुण दोशी, पूनम पूनावाला, कल्पेश चव्हाण तथा मिसेज विजयता सुर्वे शामिल रहे। सभी उपस्थित सदस्यों ने नागरिकों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया। इस दौरान अपर्णा पाटील ने कहा कि वे हमेशा नागरिकों की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं।